बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

मुख्य संवाददाता : इन्द्रजीत सिंह मो. 9582093548

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 21 ● अंक: 173 ● नई दिल्ली ● बुधवार 23 फरवरी 2022 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 8

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष

मो. 08750202102

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन

बी-2/370, सुल्तानपुरी

दिल्ली-86

सपा प्रमुख अखिलेश यादव के खिलाफ सैफई में दर्ज हुआ मामला

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में तीन चरण के मतदान संपन्न हो चुके हैं। इसी बीच समाजवादी पार्टी (सपा) प्रमुख अखिलेश यादव के खिलाफ सैफई में आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में मामला दर्ज हुआ है। दरअसल, अखिलेश यादव ने मतदान के दौरान अपने गृह क्षेत्र में मीडियाकर्मियों के साथ बातचीत की थी। जिसे लेकर उनके खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, एसडीएम सैफई ने बताया कि सैफई पुलिस स्टेशन में सपा प्रमुख अखिलेश यादव के खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में मामला दर्ज किया गया है।

गुजरात में भाजपा के 14 साल के राज में हुआ 6,000 करोड़ का कोयला घोटाला-कांग्रेस

कांग्रेस ने गुजरात की भाजपा सरकार पर 6,000 करोड़ रुपये के कोयला घोटाले का आरोप लगाया है। कांग्रेस का कहना है कि इस मामले की सुप्रीम कोर्ट के किसी मौजूदा जस्टिस की निगरानी में तय समय में जांच होनी चाहिए। विपक्षी पार्टी ने यह भी कहा कि प्रवर्तन निदेशालय, सीबीआई और अन्य केंद्रीय एजेंसियों को मामला दर्ज करना चाहिए। इस आरोप पर भाजपा या गुजरात सरकार की तरफ से फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक खबर का हवाला देते हुए ट्वीट किया, 60 लाख टन कोयला गायब! क्या इस कोयला घोटाले पर प्रधान मित्र मंत्री जी कुछ कहेंगे? पार्टी प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने कहा, संप्रग सरकार ने छोटे उद्योगों को किफायती दर पर अच्छी गुणवत्ता वाला कोयला उपलब्ध कराने की नीति 2007 में शुरू की थी। इसके तहत राज्यों से कहा गया था कि कोल इंडिया की खदानों से उनके पास कोयला सीधे पहुंच जाएगा और वे छोटे उद्योगों को कोयला मुहैया करा दें। लेकिन गुजरात सरकार ने खुद यह काम करने के बजाय कुछ एजेंसियों को दे दिया। वल्लभ ने आरोप लगाया, 60 लाख टन कोयला जो छोटे उद्योगों को मिलना चाहिए था, उसे राज्य के बाहर दूसरे उद्योगों को कई गुना भाव पर दे दिया गया। इसकी कीमत 6000 करोड़ रुपये है। यह छह हजार करोड़ रुपये का घोटाला है।वल्लभ ने दावा किया, पिछले 14 साल में गुजरात के उद्योग विभाग ने ये एजेंसियों नहीं बदलीं। जबकि दूसरे राज्यों में उद्योग विभाग स्वयं यह काम कर रहा है। पहले नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री होने के साथ राज्य के उद्योग मंत्री थे। इसके बाद विजय रूपाणी और भूपेंद्र पटेल भी मुख्यमंत्री होने के साथ उद्योग मंत्री रहे।

सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान न्यायाधीश की देखरेख में हो जांच

उन्होंने कहा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान न्यायाधीश की देखरेख में समयबद्ध जांच हो और 2007 से अब तक के सभी मुख्यमंत्रियों की भूमिका की भी जांच हो। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि इस संबंध में सीबीआई, ईडी और अन्य एजेंसियों को मामला दर्ज करना चाहिए।

कोयला घोटाला पर राहुल गांधी ने पीएम मोदी से मांगा जवाब

कांग्रेस प्रवक्ता गौरव बल्लभ ने बुधवार को बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले 14 साल से गुजरात में एक मॉडल चल रहा था। खूब खाऊंगा और खूब खाने दूंगा। गुजरात ने छोटे उद्योगों को दिए जाने वाले कोयले का घोटाला कर अन्य राज्यों को बेच दिया। कांग्रेस ने बीजेपी पर केंद्र और गुजरात में 6 हजार करोड़ का घोटाला करने का आरोप लगाया है। पार्टी का आरोप है कि इससे राज्य के हजारों छोटे उद्योग बंद हो गए। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि 60 लाख टन कोयला गायब! क्या इस कोयला घोटाले पर प्रधानमंत्री जी कुछ कहेंगे? कांग्रेस प्रवक्ता गौरव बल्लभ ने बुधवार को गुजरात सरकार और तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल करते हुए कहा कि इस घोटाले की सीबीआई, ईडी और अन्य जांच एजेंसियों को भी स्वत- संज्ञान लेना चाहिए। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले 14 साल से गुजरात में एक मॉडल चल रहा था। खूब खाऊंगा और खूब खाने दूंगा। गुजरात ने छोटे उद्योगों को दिए जाने वाले कोयले का घोटाला कर अन्य राज्यों को बेच दिया। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि यूपीए की सरकार ने एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए स्कीम शुरू की थी। लेकिन गुजरात सरकार ने इस में भी उन्हें फायदा न देकर 6 हजार करोड़ का घोटाला कर दिया। उन्होंने कहा कि आज गुजरात में लाखों छोटे उद्योग बंद हो गए, क्योंकि उनके कोयले को दूसरे राज्यों में ज्यादा दामों पर बेच दिया गया। 1800 से 3 हजार करोड़ जो कोयला केंद्र से गुजरात सरकार को दिया उसे अन्य राज्यों को 8 से हजार रुपये प्रति टन से अधिक की कीमत पर बेचा गया। कांग्रेस ने इसे चारा घोटाले का बाप बताते हुए मांग की है कि इस लूट में कौन-कौन शामिल है, इसकी जांच होनी जरूरी है। वहीं इस मसले पर कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने एक ट्वीट में कहा, ÷गुजरात सरकार में 6,000 करोड़ रुपये का कोयला घोटाला! खदान से 60 लाख टन कोयला आया-हुआ गायब। भाजपा सरकार ने 4 निजी कंपनियों को कोयला लाने को अधिकृत किया, तीन का पता ही नकली। शायद जबाब होगा- न कोई कोयला लाया, न कोयला आया, मामला बंद, पैसा हज्म! वहीं कांग्रेस के एक अन्य नेता संजय निरूपम ने इस मामले पर ट्वीट किया, गुजरात का कोयला घोटाला चारा घोटाला का बाप है। खदान से निकला 60 लाख टन कोयला। बीच रास्ते में गायब हो गया। 6000 करोड़ रुपये की लूट। लूट में कौन-कौन शामिल है, इसकी जांच होनी जरूरी है। गुजरात में बीजेपी ने 6 हजार करोड़ का घोटाला, 60 लाख टन कोयला गायब पर प्रधानमंत्री मोदी से जवाब मांगा।

भारत में 12-18 साल के बच्चों को भी लगेगी कोरोना वैक्सीन

नई दिल्ली । भारत सरकार ने 12-18 साल की आयु वर्ग के लिए Corbeva& वैक्सीन को अंतिम मंजूरी दे दी है। भारत के औषधि महानियंत्रक ने 12-18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए बायोलॉजिकल ई के कोविड-19 वैक्सीन Corbeva& को अंतिम स्वीकृति प्रदान कर दी। बायोलॉजिकल ई. ने जानकारी देते हुए कहा, कोविड-19 के खिलाफ भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन (आरबीडी) प्रोटीन सब-यूनिट वैक्सीन कॉर्बेवैक्स को 12 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के लिए इस्तेमाल हेतु भारत के दवा नियामक से आपातकालीन उपयोग की मंजूरी मिल गई है। बता दें कि देश में कोरोना महामारी के खिलाफ टीकाकरण अभियान जारी है। ऐसे में भारत सरकार ने पिछले साल बायोलॉजिकल ई की कॉर्बेवैक्स को मंजूरी दी थी। हालांकि आज इसे DCGI की अंतिम मंजूरी भी मिल गई है। ये टीका 12-18 वर्ग के लाभार्थियों को दिया जाएगा। इससे पहले देश में केवल 15-18 साल या उससे ऊपर के लाभार्थियों को कोरोना वैक्सीन दी जा रही है। ज्ञात हो कि भारत सरकार ने कॉर्बेवैक्स की 5 करोड़ खुराक की खरीद के आदेश दिए हैं। जिसकी कीमत 145 रुपये होगी। बता दें कि पिछले साल दिसंबर में कोरोना के बूस्टर डोज के लिए हैदराबाद की कंपनी बायोलॉजिकल ई. लिमिटेड की कॉर्बेवैक्स वैक्सीन को ट्रायल की मंजूरी मिली थी। कंपनी की योजना हर महीने 7.5 करोड़ डोज बनाने की है। कंपनी का कहना है कि फरवरी 2022 से वह हर महीने 10 करोड़ से अधिक वैक्सीन खुराक का उत्पादन करेगी।

इंफाल की रैली में बोले राहुल गांधी, कोविड के लिए पीएम का समाधान था- थाली बजाओ

नई दिल्ली । मणिपुर में 28 फरवरी को पहले चरण का मतदान है। पहले फेज के वोटिंग से पहले प्रचार के लिए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी इंफाल पहुंचे। जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। राहुल गांधी ने इस दौरान बीजेपी से लेकर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ पर जमकर निशाना साधा। राहुल ने कहा कि भाजपा का विजन, विचारधारा, विचार और भाषा है जो अन्य सभी विचारों, भाषाओं और विचारधाराओं से श्रेष्ठ है। जब भाजपा और आरएसएस मणिपुर आते हैं तो वे इस समझ के साथ नहीं आते। उनमें श्रेष्ठता की भावना आती है। मैं श्रेष्ठता की भावना से नहीं विनम्रता के साथ आता हूं। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने 2014 में खुब वायदे किए थे लेकिन वह अब 2 करोड़ रोज़गार, 15 लाख रुपये देने की बात, किसान की आय दोगुनी करने की बात, नोटबंदी और गलत तरह से जीएसटी लागू करने की बातें क्यों नहीं करते हैं? मणिपुर की जनता यह सवाल उनसे पूछें जब वह यहां आएं। कोविड के दौरान भाजपा की कार्रवाइयों ने छोटे व्यवसायों को चोट पहुंचाई है। भारत की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी गई। सत्ता में आने पर कांग्रेस मणिपुर में एमएसएमई क्षेत्र को पुनर्जीवित करेगी। हम खाद्य प्रसंस्करण और पर्यटन पर ध्यान केंद्रित करेंगे।

जब आप परेशानी में थे तो मोदी-योगी सरकार ने आपकी ओर से मुंह फेर लिया - सोनिया गांधी

नई दिल्ली ।

यूपी में कल तीसरे चरण के लिए चुनाव सम्पन्न हो गया है. इसके साथ ही अब चौथे चरण के लिए मतदान होने वाले हैं. इस बीच सभी पार्टियां पूरे दम-खम के साथ प्रचार करने में लगी है. इस फेज में अयोध्या सहित कुछ सीटें बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जा रहीं है जहां से कई दिग्गज नेता चुनावी मैदान में है. चौथे फेज के चुनाव के लिए आज प्रचार का अंतिम दिन है. इस दौरान आज कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए मतदाताओं को संबोधित किया. जनता को एड्रेस करने के साथ ही सोनिया गांधी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा. सोनिया ने कहा, आपने पांच साल में ऐसी सरकार देखी है जिसने

अलगाव पैदा करने के अलावा कुछ नहीं किया. उन्होंने कहा इस सरकार में फसलें बर्बाद हुई है. देश में इतनी बेरोजगारी है कि बीजेपी सरकार ने आपको घर बिठा दिया है. देशभर में 12 लाख सरकारी पद खाली है लेकिन भर्तियां नहीं हो रही है. सोनिया ने महंगाई का मुद्दा उठाते हुए कहा कि रसोई गैस, सरसो तेल के इतने दाम बढ़ गए की लोग घर में गैस लेने की जगह चूल्स का

***सोनिया गांधी का बीजेपी पर निशाना, बोलीं- सरकार ने आपको घर पर बिठा दिया, जरूरत के वक्त आंखें मूंद लीं; ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण**

इस्तेमाल कर रहे हैं. महंगाई ने लोगों का जीवन दूभर कर दिया है. वहीं सोनिया गांधी ने कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी के मुद्दे पर भी केंद्र को घेरा है. उन्होंने कहा, एक तरफ ऑक्सीजन की कमी है तो दूसरी तरफ लोगों को इलाज के लिए दवाई नहीं मिल रही है. वहीं लॉकडाउन में काम बंद हो गय. यह मोदी-योगी सरकार का गैर-जिम्मेदाराना सरकार का परिचय दिया है. उन्होंने कहा कि देश में बेरोजगारी बढ़ गई है.

हिजाब आवश्यक धार्मिक परंपरा नहीं: हाईकोर्ट में बोली कर्नाटक सरकार, इसे शैक्षणिक संस्थानों से बाहर रखा जाना चाहिए

बेंगलुरु ।

कर्नाटक सरकार ने सोमवार को उच्च न्यायालय से कहा कि हिजाब एक आवश्यक धार्मिक प्रथा नहीं है और इसे शैक्षणिक संस्थानों से बाहर रखा जाना चाहिए। इस मामले पर पिछले कई दिनों से सुनवाई चल रही है और सुनवाई आज दोपहर 2.30 बजे फिर से शुरू होगी। हिजाब मामले की सुनवाई कर रहे कर्नाटक उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ से राज्य के महाधिवक्ता प्रभुलिंग नावडगी ने कहा, ''हमारा यह रुख है कि हिजाब एक आवश्यक धार्मिक परंपरा नहीं है। डॉ. भीम राव आंबेडकर ने संविधान सभा में कहा था कि 'हमे अपने धार्मिक निर्देशों को शैक्षणिक संस्थानों के बाहर रख देना चाहिए।''ऑनलाइन वेबसाइट लाइव लॉ के अनुसार, बसवराज

बोम्मई सरकार की ओर से पेश होते हुए महाधिवक्ता प्रभुलिंग नावडगी ने अदालत में तर्क दिया, यह निर्धारित करने के लिए तीन टेस्ट हैं कि क्या कोई प्रथा आवश्यक धार्मिक प्रथा है। क्या यह मूल विश्वास का हिस्सा है? क्या यह प्रथा उस धर्म के लिए मौलिक है? यदि उस प्रथा का पालन नहीं किया जाता है, तो क्या धर्म का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा?

अदालत ने पूछा सीधा सवाल, इजाजत है या नहीं?

मुख्य न्यायाधीश ने सवाल किया, ''आपने दलील दी है कि सरकार का आदेश नुकसान नहीं पहुंचाएगा और राज्य सरकार ने हिजाब को प्रतिबंधित नहीं किया है तथा ना ही इस पर कोई पाबंदी लगाई है। सरकारी आदेश में कहा गया है कि छात्राओं को निर्धारित पोशाक पहनना चाहिए। आपका क्या रुख है-- हिजाब को शैक्षणिक संस्थानों में अनुमति दी जा सकती है, या नहीं? ''नावडगी ने जवाब में कहा कि यदि संस्थानों को इसकी अनुमति दी जाती है तब यह मुद्दा उठने पर सरकार संभवत कोई निर्णय करेगी। उन्होंने कहा कि सरकारी आदेश का सक्रिय हिस्सा इस संबंध में निर्णय लेने के लिए संस्थानों पर छोड़ देता है। उन्होंने कहा, सरकारी आदेश संस्थानों को यूनिफॉर्म तय करने की पूरी स्वायत्तता देता है। कर्नाटक शिक्षा अधिनियम की प्रस्तावना एक धर्मनिरपेक्ष वातावरण को बढ़ावा देना है।

चारा घोटाला: लालू यादव को 5 साल की सजा और 60 लाख का जुर्माना

पटना ।

रांची में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एक विशेष अदालत ने सोमवार को राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता लालू प्रसाद यादव को 139 करोड़ रुपये के चारा घोटाला मामले में पांच साल कैद की सजा सुनाई और उन पर 60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। राजद सुप्रीमो को इस मामले में 15 फरवरी को दोषी ठहराया गया था और आज यानी 21 फरवरी को सजा सुनाई गई। सीबीआई कोर्ट ने लालू यादव को डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ की अवैध निकासी का दोषी पाया है। सजा के बाद लालू यादव ने ट्वीट कर कहा कि वो हरा नहीं सकते इसलिए साजिशों से फँसाते है। लालू यादव ने लिखा, अन्याय असमानता से, तानाशाही जुल्मी सत्ता से, लड़ा हूँ लड़ता रहूँगा, डाल कर आँखों में आँखें, सच जिसकी

***सजा के बाद लालू यादव का पहला रिएक्शन, बोले- वो हरा नहीं सकते इसलिए साजिशों से फंसाते हैं**

ताकत है, साथ है जिसके जनता, उसके हौसले क्या तोड़ेंगी सलाखें। उन्होंने आगे लिखा, मैं उनसे लड़ता हूँ जो लोगों को आपस में लड़ाते है, वो हरा नहीं सकते इसलिए साजिशों से फँसाते है। ना डरा ना झुका, सदा लड़ा हूँ, लड़ता ही रहूँगा, लड़ाकों का संघर्ष कायरों को ना समझ आया है ना आएगा। पिछले हफ्ते दोषी ठहराए जाने के बाद होटवार जेल से राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स), रांची में स्थानांतरित किए गए 73 वर्षीय बुजुर्ग राजनेता को पहले झारखंड में दुमका, देवघर और चाईबासा कोषागार से जुड़े चार अन्य मामलों में 14 साल जेल की सजा सुनाई गई थी।

कर्नाटक : बजरंग दल सदस्य की हत्या के बाद शिवमोगा में आगजनी, तोड़फोड़, पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले

घटना के बाद तीन आरोपी गिरफ्तार, शिवमोगा में स्कूल-कॉलेज बंद, धारा 144 लागू

बेंगलुरु ।

हिन्दूवादी संगठन बजरंग दल के एक कार्यकर्ता की हत्या के बाद कर्नाटक के शिवमोगा शहर में भारी तनाव है. उपद्रवियों ने शहर के अंदर कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया है तो कई जगह तोड़फोड़ पथराव भी की है. घटना के बाद एहतियातन शहर में धारा 144 लागू कर दी गई है. पुलिस ने यह जानकारी दी है. पुलिस ने उपद्रवियों पर आंसू गैस के गोले भी दागे हैं. दर्जी का काम करने वाले बजरंग दल के 26 वर्षीय कार्यकर्ता हर्ष को कल (रविवार, 20 फरवरी) रात करीब 9 बजे अज्ञात लोगों ने चाकू मार दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. बाद में उसे अस्पताल ले जाया गया लेकिन उसे बचाया

नहीं जा सका. इस हमले के बाद, गुस्साए लोगों ने इलाके के कई वाहनों में आग लगा दी. आगजनी को रोकने के लिए पुलिस ने इलाके में भारी बल तैनात किया है. इसके अलावा प्रशासन ने सार्वजनिक समारोहों पर प्रतिबंध लगा दिया है. प्रशासन ने अगले आदेश तक स्कूल और कॉलेजों को बंद रखने का आदेश दिया है. पाबंदी के बावजूद, बजरंग दल के समर्थकों की भारी भीड़ युवक के शव को घर ले जाने के दौरान साथ दिखी. राज्य के गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र ने कहा है कि अब तक की जांच में हत्या और हिजाब विवाद के बीच कोई संबंध सामने नहीं आया है. उन्होंने कहा, हिजाब मुद्दे का इस घटना से कोई लेना-देना नहीं है. यह अलग-अलग कारणों से हुआ है. शिवमोगा एक संवेदनशील शहर है. कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज एस बोम्मई ने कहा है कि पुलिस को जांच के दौरान कई अहम सुराग मिले हैं और वह उन पर काम कर रही है. इस बीच, कर्नाटक के ग्रामीण विकास मंत्री केएस ईश्वरप्पा ने कर्नाटक कांग्रेस के प्रमुख डीके शिवकुमार पर हिजाब विवाद में की गई उनकी टिप्पणियों को ही हत्या के लिए उकसाने का कारण होने का आरोप लगाया है. ईश्वरप्पा ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार पर आरोप लगाया कि उनके बयान ने अल्पसंख्यक समुदाय में असामाजिक तत्वों को उकसाया है. मंत्री ने हर्ष को एक ईमानदार व्यक्ति बताया. उन्होंने कहा, मुस्लिम गुंडों ने उसकी हत्या कर दी. हाल ही में डीके शिवकुमार ने दावा किया था कि राष्ट्रीय ध्वज को भगवा ध्वज से बदल दिया गया और हिजाब विवाद के विरोध के लिए सूरत में एक कारखाने से लगभग 50 लाख भगवा शॉल मंगवाए गए थे. उनके इन बयानों के बाद ही गुंडागर्दी बढ़ी. ईश्वरप्पा की टिप्पणी का जवाब देते हुए, डीके शिवकुमार ने कहा कि वह एक पागल आदमी हैं. पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने भी कहा है, उनकी (ईश्वरप्पा) जुबान और दिमाग के बीच कोई संबंध नहीं है. भाजपा नेतृत्व को उन्हें बर्खास्त कर देना चाहिए. विधानसभा में विपक्ष के नेता सिद्धारमैया ने आरोप लगाया है कि राज्य के गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र राज्य में कानून और व्यवस्था को संभासने में विफल रहे हैं. इसलिए उन्हें तत्काल पद छोड़ देना चाहिए.

ट्रेन टिकट की बुकिंग से लेकर बैंक खाते का बैलेंस भी बताएंगे कोटेदार, सीएससी की सारी सुविधाएं मिलेंगी राशन की दुकान पर

नई दिल्ली।

केंद्र सरकार लंबे समय से समाज के अंतिम तबके तक डिजिटल और वित्तीय सेवाएं पहुंचाने की दिशा में काम कर रही है। इसी के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय राशन की दुकानों या फेयर प्राइस शॉप (एफपीएस) के जरिए देश के कोने-कोने तक डिजिटल और वित्तीय वित्तीय सेवाएं पहुंचाने को लेकर नई योजना पर काम कर रहा है। मंत्रालय अगले एक वर्ष में पूरे देश में 10 हजार से अधिक सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) को एफपीएस से जोड़ने की योजना बना रहा है। वर्तमान में करीब 8 हजार सीएससी राशन की दुकानों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इस संबंध में सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के बीच समझौता ज्ञापन में बदलाव किया जाएगा। इस कदम से राशन की दुकानों का संचालन करने वालों को कमाई के अतिरिक्त मौके मिलेंगे। साथ ही आम लोगों को अपने पास-पड़ोस में ही वित्तीय सेवाएं उपलब्ध होंगी। अभी उत्तराखंड, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान और तमिलनाडु में स्थित राशन की दुकानों से वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। वर्तमान में देश में 3 लाख से ज्यादा सीएससी कार्यरत हैं। यह सीएससी लोगों को इलेक्ट्रॉनिक सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। इसमें आधार और पैन कार्ड का पंजीकरण, रेल टिकट की बुकिंग, गानों की डाउनलोडिंग, बैंक खाते के

बैलेंस की जानकारी और ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए चल रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी से जुड़ी सेवाएं शामिल हैं। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की तहत मंत्रालय की योजना सीएससी की कवरेज को बढ़ाकर 6 लाख गावों तक पहुंचाने की है। देश में राशन की 5.34 लाख दुकानेंमौजूदा समय में देश में राशन की कुल 5.34 लाख दुकानें हैं। इन दुकानों के जरिए हर वर्ष 80 करोड़ से अधिक लोगों को 60 से 70 मिलियन टन अनाजों का वितरण हो रहा है।

एक आधिकारिक सूत्र के मुताबिक, एफपीएस पर हर महीने बड़ी संख्या में लोग राशन लेने जाते हैं। ऐसे में इन दुकानों पर अतिरिक्त आय पैदा करने की गुजाइश है। खाद्य मंत्रालय वित्तीय सेवाएं देने वाले एफपीएस को अलग कलर कोड देने की योजना पर काम कर रहा है। इससे इन एफपीएस की सार्वजनिक सेवाएं डिलिवरी पॉइंट के रूप में अलग पहचान हो सकेगी। साथ ही खाद्य मंत्रालय, वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवाएं विभाग और भारतीय स्टेट बैंक ने संयुक्त रूप से एक योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत एफपीएस डीलर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। इस लोन के जरिए एफपीएस डीलर आवश्यक खाद्य और गैर खाद्य वस्तुओं की बिक्री के लिए भवन का निर्माण कर सकते हैं।

सरकार एफपीएस के कामकाज में सुधार को लेकर भी कई उपाय अपना रही है। इसके तहत राशन कार्डों का डिजिटाइजेशन किया जा रहा है। राशन कार्डों को आधार कार्ड से जोड़ा जा रहा है। साथ ही एफपीएस पर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल (ईपीओएस) मशीनों से जोड़ा जा रहा है। अभी तक देश की कुल 5.34 लाख एफपीएस में से 95 फीसदी को ईपीओएस मशीनों से जोड़ा जा चुका है।

एक नजर

कमजोर वैश्विक संकेतों के बीच टूटा शेयर बाजार, सेंसेक्स 500 अंक फिसला, निफ्टी 17200 के नीचे

नई दिल्ली । सप्ताह के पहले कारोबारी दिन सोमवार को भी शेयर बाजार पर बीते हफ्ते की सुस्ती दिखाई दी और दोनों सूचकांक लाल निशान पर खुला। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) का 30 शेयरों वाला सूचकांक सेंसेक्स 228 अंक टूटकर 57,604 के स्तर पर खुला। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) के निफ्टी सूचकांक ने 77 अंक की तेजी लेते हुए 17,198 के स्तर पर कारोबार की शुरुआत की। घंटेभर के कारोबार के दौरान ही सेंसेक्स 500 अंक से ज्यादा टूट चुका है। फिलहाल, सेंसेक्स 518 अंक फिसलकर 57,314 के स्तर पर, जबकि निफ्टी 165 अंक की गिरावट के साथ 17,110 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। बीते कारोबारी सत्र शुक्रवार को शेयर बाजार दिनभर उतार-चढ़ाव भरे कारोबार के बाद अंत में लाल निशान पर बंद हुआ था। सेंसेक्स 59 अंक टूटकर 57,833 के स्तर पर बंद हुआ था, जबकि निफ्टी 28 अंक फिसलकर 17,276 के स्तर पर बंद हुआ था। गौरतलब है कि 18 फरवरी को समाप्त सप्ताह में भी भारतीय इक्विटी बाजार गिरावट के साथ लाल निशान पर रहा। यह लगातार दूसरा हफ्ता है जबकि बाजार में गिरावट का दौर जारी है। इस हफ्ते में बीएसई स्मॉलकैप इंडेक्स 3 फीसदी से ज्यादा टूटा, तो वहीं मिडकैप इंडेक्स में 2 फीसदी की कमी आई। लॉर्ज कैप इंडेक्स की बात करें तो इसमें 0.7 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है। लगातार दो हफ्ते से जारी शेयर बाजार के बुरे दौर की वजह को देखें तो बढ़ता जियोपॉलिटिकल तनाव, कच्चे तेल की कीमतों में तेजी और लगातार हो रही विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) की बिकवाली गिरावट के सबसे प्रमुख कारण रहे हैं। गौरतलब है कि पिछले हफ्ते बाजार एक साल में सबसे बड़ी एक दिनी गिरावट के साथ शुरु हुआ था, हालांकि इसके बाद अगले दिन कुछ रिकवरी आती दिखी। लेकिन ये तेजी एक दिन ही रही और हफ्ते के बाकी 3 दिनों में बाजार ने फिर गिरावट देखी।

तकनीकी खराबी ने चित्रा रामकृष्ण को बनाया एनएसइ का सीईओ, अज्ञात बाबा के इशारे पर लेती थीं फैसला

नई दिल्ली। एनएसई की परिष्कृत एल्गोरिदम आधारित सुपरफास्ट ट्रेडिंग में तकनीकी खराबी आने से शेयर कारोबार की पुरुष प्रधान दुनिया में चित्रा रामकृष्ण को एनएसई के शीर्ष पद पर आने का मौका मिला था। एनएसई में पांच अक्टूबर 2012 की सुबह आई इस तकनीकी खराबी से निवेशकों की संपत्ति 10 लाख करोड़ रुपये घट गई थी। इसके बाद एनएसई के तत्कालीन सीईओ रवि नारायण को पद छोड़ना पड़ा और कुछ महीने बाद, 13 अप्रैल 2013 को एनएसई की कमान औपचारिक रूप से चित्रा रामकृष्ण को सौंप दी गई। चित्रा रामकृष्ण हिमालय में रहने वाले किसी अज्ञात बाबा के इशारे पर कई फैसले लेती थीं। दरअसल, तकनीक की खराबी ने ही चित्रा रामकृष्ण को एनएसई में शीर्ष पद पर पहुंचाया था, इसीलिए उन्होंने आठ साल पहले एक साक्षात्कार में कहा था कि प्रौद्योगिकी एक ऐसा शेर है, जिस पर हर कोई सवार है। एनएसई ने साल 1994 में अपनी शुरुआत के एक साल में ही देश के सबसे बड़े शेयर बाजार के तौर पर 100 साल पुराने बीएसई को पछाड़ दिया था। आज 59 वर्षीय चित्रा रामकृष्ण एक अजीबोगरीब घोटाले में फंस गई हैं। पूंजी बाजार नियामक सेबी की जांच से यह पता चला है कि एक्सचेंज के प्रमुख व्यावसायिक फैसले लेने के लिए एक गुमनामी बाबा निर्देश देते थे। एक पूर्व शीर्ष नियामक अधिकारी ने कहा कि शीर्ष प्रबंधन और कुछ प्रमुख निदेशक स्पष्ट रूप से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफल रहे। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि देश में लगभग हर नियामक, प्रशासनिक एजेंसी और जांच एजेंसी इस मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रही हैं और जांच के दायरे में उन सभी निदेशकों को शामिल किया गया है, जो इन वर्षों के दौरान एनएसई बोर्ड में रहे। जांच सिर्फ योगी की पहचान सुनिश्चित करने तक ही सीमित नहीं है बल्कि बोर्ड, नियामक और सरकार सहित विभिन्न स्तरों पर चूक के कारणों का भी पता लगाया जा रहा है। एक पूर्व नियामक ने कहा कि ऐसा लगता है कि पूर्व और सेवारत नौकरशाहों, कुछ अत्यधिक महत्वाकांक्षी दलालों, शीर्ष सरकारी अधिकारियों और एक्सचेंज में शामिल कुछ कारपोरेट अधिकारियों की एक मंडली ने अपने निजी फायदे के लिए विभिन्न खामियों को पैदा किया और उसका फायदा उठाया।

सिंगापुर में क्रिप्टोकरंसी घोटाले के जरिये सबसे ज्यादा नुकसान, 90 फीसदी ग्रेजुएट या इससे ज्यादा शिक्षित बने शिकार

सिंगापुर। सिंगापुर के निवेशकों को पिछले तीन वर्षों में किसी अन्य धोखाधड़ी की तुलना में फर्जी निवेश योजनाओं में सबसे अधिक नुकसान हुआ है। विशेष रूप से वे चीनी मूल के पिग-बूचरिंग क्रिप्टोकरंसी घोटाले का सबसे बड़ा शिकार बने हैं। निवेशकों को पिछले साल इस तरह की योजनाओं से 19.09 करोड़ सिंगापुर डॉलर का नुकसान हुआ है। यह आंकड़ा 2019 के 3.69 करोड़ डॉलर का पांच गुना से अधिक है। द संडे टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, इस तरह की धोखाबाजी को अंजाम देने वाले निवेशकों से ऐसी योजनाओं में निवेश करने का आग्रह करने से पहले उनके साथ रिश्ता बनाने में महीनों लगाते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि सिंगापुर में हाल में पिग बूचरिंग घोटाला सामने आया है। इसमें चीनी शब्द शा झू पान का इस्तेमाल किया गया है, जिसका अर्थ वध करने से पहले एक सुअर को मोटा करने से है। इसे अपराधियों ने खुद अपने घोटाले का वर्णन करने के लिए गढ़ा था। जालसाज फर्जी निवेश योजनाओं में निवेश करने का आग्रह करने से पहले लक्ष्य यानी निवेशकों के साथ नजदीकी बनाने में महीनों लगाते हैं। सिंगापुर दैनिक ने समाचार रिपोर्टों का हवाला देते हुए कहा कि 2016 में चीन में इस तरह के घोटाले शुरू हुए। उस समय घोटालेबाजों ने पीड़ितों को नकली जुए की वेबसाइटों पर दांव लगाने के लिए तैयार किया। चीनी सरकार ने 2018 में अवैध सट्टेबाजी पर नकेल कसी, लेकिन जालसाजों ने फिर दक्षिण-पूर्व एशिया में चीनी भाषी प्रवासियों को निशाना बनाया। जैसे-जैसे यूरोप और अमेरिका में जनसांख्यिकी का विस्तार हुआ, क्रिप्टोकरंसी निवेश की बढ़ती लोकप्रियता के साथ-साथ घोटाले की रणनीति विकसित हुई। सिंगापुर पुलिस के मुताबिक, पीड़ितों के निवेश की राशि को चीन और हांगकांग के बैंकों में हस्तांतरित किया जाता है। इसके बाद पीड़ितों को मुनाफा वसूलने के लिए प्रशासनिक शुल्क, सुरक्षा शुल्क और करों का भुगतान करने के लिए कहा जाता है। पुलिस के मुताबिक, कई मामलों में पीड़ितों को शुरुआती चरण में लाभ होता है। इससे उन्हें निवेश के वैध और आकर्षक होने का भरोसा हो जाता है। एक बार बड़ी राशि निवेशक के खाते में जमा होने के बाद जालसाज संपर्क से बाहर हो जाते हैं। वैसे तो पिग बूचरिंग का वार्षिक आधार पर कोई आधिकारिक डाटा उपलब्ध नहीं है। हालांकि, पिग बूचरिंग की पहचान को लेकर बनाए गए एक संगठन के अनुसार, 30-40 साल के प्रोफेशनल इसके ज्यादा शिकार होते हैं। ऐसे घोटालों की 70 फीसदी शिकार महिलाएं हैं, जिनकी उम्र 25 से 40 वर्ष के बीच है। घोटालों के पीड़ितों में 90 फीसदी स्नातक या इससे ज्यादा शिक्षित शामिल हैं।

15000 रुपये से अधिक बेसिक सैलरी वालों के लिए नई पेंशन योजना पर विचार कर रही मोदी सरकार

नई दिल्ली। संगठित क्षेत्र के 15,000 रुपये से अधिक का मूल वेतन पाने वाले तथा कर्मचारी पेंशन योजना-1995 (ईपीएस-95) के तहत अनिवार्य रूप से नहीं आने वाले कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन योजना लाने पर विचार कर रहा है। वर्तमान में संगठित क्षेत्र के वे कर्मचारी जिनका मूल वेतन (मूल वेतन और महंगाई भत्ता) 15,000 रुपये तक है, अनिवार्य रूप से ईपीएस-95 के तहत आते हैं। एक सूत्र के मुताबिक, पीएफओ के सदस्यों ने ऊंचे योगदान पर अधिक पेंशन की मांग की है। इस प्रकार उन लोगों के लिए एक नया पेंशन उत्पाद या योजना लाने के लिए सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है, जिनका मासिक मूल वेतन 15,000 रुपये से अधिक है। सूत्र के अनुसार, इस नए पेंशन उत्पाद पर प्रस्ताव 11 और 12 मार्च को गुवाहाटी में ईपीएफओ के निर्णय लेने वाले शीर्ष निकाय केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) की बैठक में आ सकता है। बैठक के दौरान सीबीटी की ओर से नवंबर, 2021 में पेंशन संबंधी मुद्दों पर गठित एक उप-समिति भी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। सूत्र ने बताया कि ऐसे ईपीएफओ अंशधारक हैं जिन्हें 15,000 रुपये से अधिक का मासिक मूल वेतन मिल रहा है, लेकिन वे ईपीएस-95 के तहत 8.33 प्रतिशत की कम दर से ही योगदान कर पाते हैं। इस तरह उन्हें कम पेंशन मिलती है।

तेल कंपनियों ने जारी किए पेट्रोल-डीजल के दाम

नई दिल्ली ।

सरकारी तेल कंपनियों की ओर से आज पेट्रोल-डीजल के दामों में कोई बदलाव नहीं किया है। आज भी दाम स्थिर हैं। पिछले कई महीनों से देश कई राज्यों में अभी भी पेट्रोल के दाम 100 रुपये से ऊपर चल रहे हैं। देश में तेल के दाम अभी आम आदमी की जेब पर असर डाल रहे हैं। दिल्ली में पेट्रोल का दाम 95.41 रुपये जबकि डीजल का दाम 86.67 रुपये प्रति लीटर है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 109.98 रुपये व डीजल की कीमत 94.14 रुपये प्रति लीटर है। कोलकाता में पेट्रोल का दाम 104.67 रुपये जबकि डीजल का दाम 89.79 रुपये लीटर है। वहीं चेन्नई में भी पेट्रोल 101.40 रुपये लीटर है तो डीजल 91.43 रुपये लीटर है। बता दें कि मध्यप्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, ओडिशा, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में पेट्रोल का भाव 100 रुपये चल रहा है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत सबसे अधिक है। पेट्रोल-डीजल की कीमत आप एसएमएस के जरिए भी जान सकते हैं। इंडियन ऑयल की वेबसाइट पर जाकर आपको अपने शहर का कोड लिखकर 9224992249 नंबर पर भेजना होगा। हर शहर का कोड अलग-अलग है, जो आपको आईओसीएल की वेबसाइट से मिल जाएगा। बता दें कि प्रतिदिन सुबह छह बजे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव होता है। सुबह छह बजे से ही नई दरें लागू हो जाती हैं। पेट्रोल व डीजल के दाम में एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन और अन्य चीजें जोड़ने के बाद इसका दाम लगभग दोगुना हो जाता है। इन्हीं मानकों के आधार पर पर पेट्रोल रेट और डीजल रेट रोज तय करने का काम तेल कंपनियां करती हैं। डीलर पेट्रोल पंप चलाने वाले लोग हैं। वे खुद को खुदरा कीमतों पर उपभोक्ताओं के अंत में करों और अपने स्वयं के मार्जिन जोड़ने के बाद पेट्रोल बेचते हैं। पेट्रोल रेट और डीजल रेट में यह कॉस्ट भी जुड़ती है।

सोने का दाम 50000 पर बरकरार, चांदी की कीमत फिसली, पीली धातु में तेजी की ये है बड़ी वजह

नई दिल्ली।

अगर आप आभूषण खरीदने का मन बना रहे हैं तो पहले आपकों इन कीमती धातुओं के ताजा भाव जान लेना आपके लिए बेहद जरूरी है। एमसीएक्स पर आज सोने की कीमत में मामूली उछाल आया। सुबह 10 बजे तक यह कीमती पीली धातु 0.02 फीसदी की तेजी के साथ 50,121 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बिक रही थी। वहीं दूसरी ओर चांदी का दाम सोमवार को 0.45 फीसदी टूटकर 63,613 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गया है। रूस-यूक्रेन के बीच जारी तनाव के बीच सोने की कीमत में इजाफा देखने को मिल रहा है।

विशेषज्ञों का मानना है कि सोने में अभी तेजी जारी रहने की पूरी संभावना है। उन्होंने संभावना जताते हुए कहा है कि वर्तमान हालात को देखते हुए अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना करेक्शन के साथ अगले तीन-चार महीनों में 2000 डॉलर के स्तर तक पहुंच सकता है। मतलब, आने वाले

दिनों में वायदा कारोबार में सोने का भाव 52 हजार रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर को पार कर सकता है। गौरतलब है कि रूस और यूक्रेन के बीच तनाव के चलते निवेशकों की धारणाओं पर गहरा असर हो रहा है और महंगाई बढ़ने की संभावना के चलते निवेशक सुरक्षित निवेश की तरफ रुख कर रहे हैं। बता दें कि भारत ही नहीं बल्कि दुनियाभर में सोने को निवेश के बेहतर विकल्प में से एक माना जाता है। यही कारण है कि सोने के भाव तेज उछाल दर्ज किया जा रहा है। फिलहाल, सोने की कीमत एक साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी है। इस बीच विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) भारतीय बाजारों से लगातार बड़ी संख्या में पैसों की निकासी कर रहे हैं। आंकड़ों को देखें तो फरवरी माह में अब तक भारतीय बाजारों से विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने 18,856 करोड़ रुपये निकाले हैं। बता दें कि यह लगातार पांचवां महीना है जब एफपीआई ने भारतीय बाजारों से पैसे बाहर निकाले हैं। रूस-यूक्रेन में बढ़े तनाव और अमेरिका में ब्याज दरों के बढ़ने की संभावना को इनके भारतीय बाजारों से पैसे निकालने की वजह माना जा रहा है। आभूषण बनाने के लिए ज्यादातर 22 कैरेट का ही इस्तेमाल होता है। कुछ लोग 18 कैरेट सोने का भी इस्तेमाल करते हैं। आभूषण पर कैरेट के हिसाब से हॉलमार्क बना होता है। 24 कैरेट सोने के आभूषण पर 999 लिखा होता है, जबकि 23 कैरेट पर 958, 22 कैरेट पर 916, 21 कैरेट पर 875 और 18 कैरेट पर 750 लिखा होता है। देश भर में सोने के आभूषणों की कीमत उत्पाद शुल्क, राज्य करों और मेकिंग चार्ज के कारण बदलती रहती है। आप अपने शहर सोने की कीमत मोबाइल पर भी चेक कर सकते हैं। इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के मुताबिक आप सिर्फ 8955664433 नंबर पर मिस्ड कॉल देकर प्राइस चेक कर सकते हैं। आप जिस नंबर से मैसेज करते हैं उसी नंबर पर आपके मैसेज आ जाएगा। इस तरह आप घर बैठे सोने के लेटेस्ट रेट जान लेंगे।

रेलवे ने लॉन्च किया नया एप, अब आसानी से बुक होगा तत्काल टिकट

नई दिल्ली।

रेल यात्रियों के लिए एक बड़ी राहत वाली खबर है। यात्री अब कन्फर्म टिकट आसानी से बुक कर सकते हैं। इसके लिए आईआरसीटीसी ने एक नया एप लॉन्च किया है, जिसे ConfirmTicket Mobile App के तहत लिस्टेड किया गया है। ConfirmTICKET भारतीय रेलवे के लिए आधिकारिक आईआरसीटीसी पार्टनर ट्रेन एप है जो यूजर्स को ट्रेन टिकट बुक करने, सीट की उपलब्धता की जांच करने, ट्रेन शेड्यूल की जांच करने और उन्हें ऑफ़लाइन एक्सेस करने की सुविधा देता है। यूजर्स एप का उपयोग करके किसी भी समय ई-टिकट के लिए टीडीआर फाइल कर सकते हैं या टिकट रद कर सकते हैं। Confirm TICKET मोबाइल एप तत्काल कोटा के तहत उपलब्ध सीटों के बारे में जानकारी देता है। ट्रेन यात्रियों के लिए जो अधिक उपयोगी

है, वह यह है कि उन्हें अपने पसंदीदा रूट के तहत अलग-अलग ट्रेनों के नाम पर फीड नहीं करना पड़ता है। इसके बजाय यह एप यूजर्स को उस विशेष मार्ग पर चलने वाली विभिन्न ट्रेनों में उपलब्ध तत्काल सीटों के सभी डिटेल के बारे में जानकारी देता है। उदाहरण के लिए X, Y, Z ट्रेनें मार्ग ए पर चलती हैं। उस स्थिति में यात्रियों को X, Y, Z ट्रेनों के लिए अलग से तत्काल टिकट की तलाश नहीं करनी होगी। एप का उपयोग करके वे रूट में चलने वाली सभी ट्रेनों के लिए सभी तत्काल सीटों की स्थिति देख सकते हैं। एप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। एप में टिकट बुकिंग के लिए एक मास्टर लिस्ट भी है जो आपकी सभी जरूरतों का ख्याल रखती है। यूजर्स अपनी बुकिंग की पुष्टि करने से पहले अपने यात्रा डिटेल को सेव कर सकते हैं। तत्काल बुकिंग मानदंडों के अनुसार, टिकट बुकिंग का समय सुबह 10 बजे से शुरू होता है। जिसके बाद यात्री अपनी ऑनलाइन बुकिंग और ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं। यात्रियों को हालांकि यह ध्यान रखना चाहिए कि इस एप के माध्यम से बुक किए गए उनके तत्काल टिकट कन्फर्म भी हो सकते हैं या वेटिंग भी मिल सकता है। इस बीच आईआरसीटीसी ने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर हाल ही में साझा किया है कि आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट एप डाउनलोड करने से ग्राहकों को टिकट बुक करने की कई सुविधा मिलेगी जो परेशानी मुक्त होगी और कम समय लगेगा। आईआरसीटीसी ने कहा कि एप कुछ ही क्लिक में ट्रेन टिकट बुक करने या उनके बारे में पूछताछ करने का एक तुरंत, आसान और सुविधाजनक तरीका देता है। टिकट 3 आसान चरणों में बुक किए जा सकते हैं जबकि यात्रियों को 24×7 सहायता भी मिलेगी।

मार्च अंत तक इंटरऑपरेबल हो जाएंगे ई-वॉलेट

नई दिल्ली। मार्च के अंत तक आपके ई-वॉलेट इंटरऑपरेबल हो सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स इंटरऑपरेबिलिटी के लिए 31 मार्च, 2022 की समय सीमा तय की थी। हालांकि, कुछ लोगों को ई-वॉलेट इंटरऑपरेबिलिटी को लेकर कंफ्यूजन हो सकता है, इसीलिए चलिए आपको बताते हैं कि आखिर इंटरऑपरेबिलिटी क्या होती है। आरबीआई के अनुसार, इंटरऑपरेबिलिटी एक टेक्निकल कम्पैटिबिलिटी है, जो एक पेमेंट सिस्टम को दूसरे पेमेंट सिस्टम के संयोजन के साथ उपयोग करने के लिए सक्षम बनाती है। पीपीआई कार्ड या ई-वॉलेट किसने जारी किया, इसके प्रभाव से बाहर यूजर्स किसी भी पेमेंट एक्सेप्टेंस प्वाइंट पर कार्ड/ई-वॉलेट का उपयोग कर सकते हैं। आरबीआई के पूर्व कार्यकारी निदेशक जी पद्मनाभन का कहना है, पेमेंट्स की दुनिया (यूपीआई) के माध्यम से पीपीआई इंटरऑपरेबिलिटी हासिल करना एक लय बदलने वाली पहल है। आरबीआई के नवीनतम दिशानिर्देशों में कहा गया है कि ऐसे मामलों में जहां पीपीआई डिजिटल वॉलेट हैं, इंटरऑपरेबिलिटी को यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) के माध्यम से प्रदान करना होगा, और जहां वे भौतिक (पेमेंट कार्ड) हैं, उन्हें कार्ड नेटवर्क पर स्वीकार्य होना चाहिए। हालांकि, कुछ मामलों में इंटरऑपरेबिलिटी लागू नहीं होगी। परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रीपेड उपकरण, जैसे मेट्रो या अन्य सार्वजनिक परिवहन कार्ड, इंटरऑपरेबिलिटी के अंतर्गत नहीं आएंगे। हालांकि, उपहार कार्ड जारी करने वाला अपने कार्ड को इंटरऑपरेबल बनाने या न बनाने का विकल्प चुन सकता है। गिफ्ट कार्ड जारी करने वालों के अलावा मर्चेंट्स अकाउंट वाले सर्विस प्रोवाइडर्स को भी इसी तरह का विकल्प दिया जाएगा। आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुरूप, भुगतान प्लेटफॉर्म जुस्पे टेक्नोलॉजीज ने ओपनपीपीआई शुरू किया है, जो डिजिटल वॉलेट को पीपीआई इंटरऑपरेबिलिटी नियमों को लागू करने और उनका पालन करने में मदद करता है। बता दें कि जुस्पे टेक्नोलॉजीज Amazon, Google, CRED, Bajaj, Ola और Swiggy जैसे व्यापारियों के लिए UPI भुगतान प्रदाता है। यह एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और यस बैंक जैसे बैंकों को भी अपनी तकनीक देता है।

ईपीएस पेंशनभोगियों को बड़ी राहत: कभी भी जमा कर सकते हैं जीवन प्रमाणपत्र, एक साल तक बनी रहेगी वैधता

नई दिल्ली ।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने पेंशनधारकों को जीवन प्रमाणपत्र जमा करने के मामले में बड़ी राहत दी है। ईपीएफओ के कर्मचारी पेंशन स्कीम 95 (ईपीएस 95) के पेंशनभोगी अब अपना जीवन प्रमाणपत्र किसी भी समय जमा करा सकते हैं।

आमतौर पर इसे नवंबर में जमा करना होता है। खास बात है कि जीवन प्रमाणपत्र जमा करने की तारीख से एक साल तक के लिए वैध होगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल के जरिये ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। दिसंबर, 2019 में ईपीएफओ ने पेंशनभोगियों की ओर से जीवन प्रमाणपत्र जमा करने के नियमों में यह बदलाव किया था।

पेंशनधारकों को पेंशन मिलना जारी रहे, इसके लिए उन्हें अपना जीवन प्रमाणपत्र जमा कराना जरूरी होता है। ईपीएफओ ने कहा, ईपीएस 95 पेंशनभोक्ता क्या आपके जीवन प्रमाणपत्र की वैधता अवधि समाप्त हो रही है? अब किसी भी समय जीवन प्रमाणपत्र जमा कर सकते हैं। यह जमा करने की एक साल की अवधि तक वैध रहेगा। कर्मचारी पेंशन स्कीम 1995 के तहत हर साल नवंबर में जीवन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने को अंतिम जीवन प्रमाणपत्र जमा करने की तारीख से एक वर्ष के बाद जीवन प्रमाण पत्र/ जीवन प्रमाण प्रस्तुत करने को प्रणाली के जरिये प्रतिस्थापित किया जा सकता है। नियम के मुताबिक, अगर किसी ईपीएस पेंशनभोगी ने 15 नवंबर, 2021 को जीवन प्रमाणपत्र जमा किया था तो उसे अब 15 नवंबर 2022 को या उससे पहले जमा करना होगा। ऐसा न करने पर पेंशन रोक दी जाएगी। पेंशनभोगियों को पेंशन प्राप्त करना जारी रखने के लिए हर साल समय-सीमा से पहले जीवन प्रमाण पत्र जमा करना जरूरी है। अगर ये अंतिम तिथि से पहले जमा नहीं करते हैं तो अगले माह से पेंशन नहीं मिलेगी।

यहां कर सकते हैं जमा

ईपीएफओ ने अपने आधिकारिक हैंडल के जरिये ट्वीट कर बताया कि ईपीएस 95 पेंशनभोगी विभिन्न जगहों पर अपना जीवन प्रमाणपत्र जमा कर सकते हैं। ट्वीट के मुताबिक, पेंशनभोगी अपना जीवन प्रमाणपत्र पेंशन जारी करने वाले बैंक, कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी), भारतीय डाक भुगतान बैंक (आईपीपीबी)/भारतीय डाकघर, उमंग एप और अपने नजदीकी ईपीएफओ कार्यालय में जाकर जमा कर सकते हैं। ईपीएफओ ने अपने ट्वीट में कहा कि पेंशनधारक ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से जीवन प्रमाणपत्र जमा करा सकते हैं। एसबीआई और पीएनबी जैसे कई सरकारी बैंक जीवन प्रमाणपत्र जमा करने के लिए डोर स्टेप सुविधा भी मुहैया करा रहे हैं।

ये दस्तावेज हैं जरूरी

जीवन प्रमाणपत्र जमा करने के लिए आपको पेंशन पेमेंट ऑर्डर (पीपीओ) नंबर, आधार नंबर, बैंक खाते की जानकारी की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए आधार से लिंक्ड मोबाइल नंबर की भी जरूरत होगी।

एक नजर

मोदी के मंत्री के गोली मारो बयान पर बिफरे सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस, सुल्ली और बुल्ली डील्स का हवाला दे पूछी हेट स्पीच की परिभाषा

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस मदन बी. लोकुर ने हेट स्पीच मामले में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के बयान का जिक्र कर कहा कि हमने दिल्ली में एक मंत्री को गोली मारो कहते सुना। यह मारने के लिए उकसाना नहीं तो क्या है? उनका कहना है कि कार्यपालिका सारे मामले पर शांत है। सुप्रीम कोर्ट भी हेट स्पीच के ऐसे मामलों में ही दखल देता है जिनमें हिंसा हो। जस्टिस लोकुर ने कहा कि एक मंत्री जो लिंचिंग के आरोपियों को माला पहनाता है, क्या वह एक सही व्यक्ति हैं? यदि ये उचित व्यक्ति है तो उचित होने का एक पूरी तरह से अलग ही अर्थ है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में हमारे पास हेट स्पीच की कोई कानूनी परिभाषा नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि हमें इसकी जरूरत है। जस्टिस लोकुर ने कहा कि कुछ समय पहले, 1969 में इंडियन पैनल कोड में संशोधन किया गया था। जस्टिस लोकुर ने कहा कि सुल्ली और बुल्ली डील्स मामले में मुस्लिम महिलाओं की नीलामी का मामला आया था। इसमें कोई हिंसा नहीं है, लेकिन क्या यह हेट स्पीच नहीं है? हरिद्वार की धर्म संसद का हवाला दे उन्होंने कहा कि अब ऐसे मामलों से निपटने को लिए संसद को कानून बनाना ही होगा। उनका कहना था कि हरिद्वार मामले में सरकार तब तक चुप रही जब तक कि सुप्रीम कोर्ट ने नहीं पूछा कि ये क्या हो रहा है।

होटल के बाथरूम में गीजर से लीक हुई गैस, दम घुटने से युवक की मौत

गुरुग्राम । गुरुग्राम स्थित एक होटल के बाथरूम में गीजर की गैस से कथित तौर पर दम घुटने के कारण एक व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि घटना के सिलसिले में होटल के मालिक और प्रबंधक के खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि राजस्थान के झुंझुनूं निवासी एवं आर्मी मेडिकल कोर में कार्यरत पंकज कुमार ने अपनी शिकायत में कहा कि वह अपने एक दोस्त के साथ उत्तराखंड की यात्रा पर गये थे। उन्होंने पुलिस को बताया कि वे 14 फरवरी को देहरादून पहुंचे तथा मसूरी, रुद्रप्रयाग, सोनप्रयाग, ऋषिकेश, हरिद्वार और दिल्ली घूमने के बाद वे 19 फरवरी को गुरुग्राम पहुंचे थे। पुलिस में दर्ज कराई गई शिकायत के मुताबिक पंकज और उनके दोस्त ने एक साथ होटल में दो कमरे बुक कराये। होटल में पंकज का दोस्त सतदेव स्नानघर में गया और करीब 25 मिनट बाद भी बाहर नहीं निकला और ना ही बुलाने पर कोई जवाब दिया। इसके बाद पंकज ने होटल के प्रबंधक से बात की। पुलिस ने बताया कि बाथरूम का दरवाजा तोड़े जाने पर सतदेव अचेत स्थिति में पाया गया और वहां धुआं भरा हुआ था। सतदेव को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पंकज ने पुलिस से कहा कि होटल मालिक और प्रबंधक की लापरवाही से यह घटना हुई। उन्होंने इस मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने सतदेव का शव उसके परिजनों को सौंप दिया है। घटना के सिलसिले में होटल मालिक और प्रबंधक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 285 (आग या ज्वलनशील सामग्री संबंधित लापरवाही), धारा 304-ए (लापरवाही से मौत), धारा 34 (साझा इरादा रखने) के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई है।

पिता ने 11 साल के बेटे को इस वजह से डांटने के बाद पीटा, मां ने दर्ज कराया मामला

नई दिल्ली । राजधानी के प्रसाद नगर इलाके में एक ऐसी घटना सामने आई है, जिसमें बच्चे को डांट लगा पिटाई करने वाले पिता के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। मां द्वारा शिकायत करने पर पिता के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। दरअसल मोबाइल पर गेम खेलने को लेकर एक शख्स ने अपने 11 साल के बेटे को डांटने के बाद उसकी पिटाई कर दी थी। इसके बाद मां बच्चे को लेकर अस्पताल पहुंची और उसने पुलिस को इस बारे में सूचित कर दिया। फिर पुलिस ने बच्चे से पूछताछ के बाद पिटाई करने वाले पिता के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मामले की जांच में जुटी पुलिस आरोपी पिता से पूछताछ कर रही है। शुरुआती जांच के बाद पुलिस को पता चला है कि बच्चे के माता-पिता के बीच कलह रहती है। इसी वजह से उसकी मां ने अपने पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस के मुताबिक 11 वर्षीय बच्चा परिवार के साथ करोल बाग इलाके में स्थित देव नगर में रहता है। उसके परिवार में माता-पिता हैं। पति-पत्नी में तकरार रहती है। छठीं कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे को मोबाइल पर गेम खेलने की लत है। दो दिन पूर्व ही उसके पिता ने उससे फोन छीनकर उसे डांट दिया। इसके बाद उसकी हल्की-फुल्की पिटाई भी कर दी। बच्चे की पिटाई करने से उसकी गाल पर निशान पड़ गए तो मां बेटे को लेकर सीधे अस्पताल पहुंच गईं। इसके बाद महिला ने अपने पति के खिलाफ पीसीआर कॉल भी कर दी। पुलिस वहां पहुंची और मामला घरेलू होने के कारण महिला को समझाने का प्रयास भी किया। लेकिन महिला बेटे की पिटाई करने पर कार्रवाई की मांग पर अड़ गई तो पुलिस ने बच्चे से पूछताछ कर मारपीट का मामला दर्ज कर लिया।

देश में कोविड-19 के उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 2,02,131 हुई

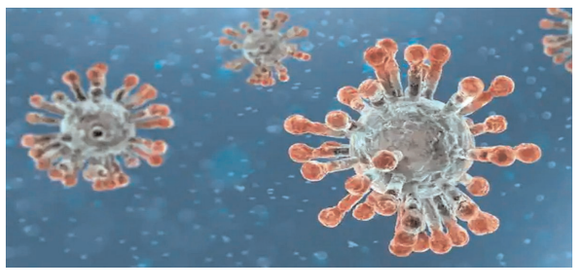

नयी दिल्ली। भारत में एक दिन में कोविड-19 के 16,051 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4,28,38,524 हो गई। पिछले 15 दिन से दैनिक मामलों की संख्या एक लाख से कम बनी हुई है। वहीं, उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 2,02,131 रह गई है। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सोमवार सुबह आठ बजे जारी किए गए अद्यतन आंकड़ों के अनुसार, देश में 206 और लोगों की संक्रमण से मौत के बाद मृतक संख्या बढ़कर 5,12,109 हो गई। देश में अभी 2,02,131 लोगों का कोरोना वायरस संक्रमण का इलाज चल रहा है, जो कुल मामलों का 0.47 प्रतिशत है। पिछले 24 घंटे में उपचाराधीन मरीजों की संख्या में 22,056 की कमी दर्ज की गई। मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर बढ़कर 98.33 प्रतिशत हो गई है। उल्लेखनीय है कि देश में सात अगस्त 2020 को संक्रमितों की संख्या 20 लाख, 23 अगस्त 2020 को 30 लाख और पांच सितंबर 2020 को 40 लाख से अधिक हो गई थी। संक्रमण के कुल मामले 16 सितंबर 2020 को 50 लाख, 28 सितंबर 2020 को 60 लाख, 11 अक्टूबर 2020 को 70 लाख, 29 अक्टूबर 2020 को 80 लाख और 20 नवंबर को 90 लाख के पार चले गए थे। देश में 19 दिसंबर 2020 को ये मामले एक करोड़ के पार हो गए थे। पिछले साल चार मई को संक्रमितों की संख्या दो करोड़ के पार और 23 जून 2021 को तीन करोड़ के पार पहुंच गई थी। इस साल 26 जनवरी को मामले चार करोड़ के पार पहुंच गए।

लखीमपुर खीरी हिंसा : आशीष मिश्रा की जमानत के खिलाफ अब मारे गए किसानों के परिजन भी पहुंचे सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली।

लखीमपुर खीरी मामले में अब किसानों के पीड़ित परिवार भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं. इन परिवारों ने भी केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को जमानत दिए जाने के फैसले को चुनौती दी है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मिश्रा को जमानत देने का फैसला सुनाया था. कार से कुचले गए मृतक किसानों के परिवारों की ओर से वकील प्रशांत भूषण के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि परिवार के सदस्यों को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर किया गया है क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने में विफल रही है. आदेश के गुण-दोष पर याचिका में कहा गया है कि हाईकोर्ट ने जमानत देते समय मिश्रा के खिलाफ बड़े सबूतों पर विचार नहीं किया क्योंकि उसके खिलाफ चार्जशीट रिकॉर्ड में नहीं लाई गई. हाईकोर्ट ने अपराध की जघन्य प्रकृति, चार्जशीट में आरोपी के खिलाफ ठोस सबूत, पीड़ित और गवाहों के संदर्भ में आरोपी की स्थिति की संभावना पर विचार किए बिना जमानत दी थी. आरोपी न्याय से भाग रहा है और अपराध को दोहरा रहा है और गवाहों के साथ छेड़छाड़ करने और न्याय के रास्ते में बाधा डालने की

संभावना है. याचिका में यह भी कहा गया है कि पीड़ितों को संबंधित सामग्री को हाईकोर्ट के संज्ञान में लाने से रोका गया क्योंकि उनके वकील 18 जनवरी, 2022 को जमानत मामले की सुनवाई से अलग हो गए थे. याचिका में कहा गया है कि वकील मुश्किल से कोई दलील दे सके और दोबारा कनेक्ट होने के लिए कोर्ट स्टाफ को बार-बार कॉल करने से कोई फायदा नहीं हुआ और पीड़ितों द्वारा हाईकोर्ट में प्रभावी सुनवाई के लिए दायर अर्जी खारिज कर दी गई. बता दें कि इससे पहले आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत को चुनौती देने की एक और अर्जी दाखिल की गई है. सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता वकील शिव कुमार त्रिपाठी और ष्ट्स पांडा ने अर्जी दाखिल की है. किसानों को अपनी जीप से कुचलने के आरोपी आशीष मिश्रा को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच से जमानत मिल गई थी. मिश्रा को लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में गिरफ्तार किया गया था. इस मामले में उत्तर प्रदेश की एसआईटी ने 5 हजार पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी. 3 अक्टूबर, 2021 को जिले के तिकुनिया इलाके में हुई हिंसा में चार किसानों समेत आठ लोगों की मौत हो गई थी. इस मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष तथा 15-20 अन्य लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया था. आशीष को 9 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था. इस घटना में कथित तौर पर भीड़ में लोगों के ऊपर एसयूवी (थार जीप) चढ़ा देने से चार किसानों की मौत हो गई थी. उसके बाद भड़की हिंसा में दो भाजपा समर्थकों, एक एसयूवी चालक और एक पत्रकार की भी मौत हो गई.

दिल्ली में अपहरण, गैंगरेप और हत्या: दुकान में मिला नाबालिग का शव, एक आरोपी गिरफ्तार

दिल्ली । राजधानी दिल्ली के नरेला इलाके में एक दुकान से नाबालिग बच्ची का शव मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस ने सोमवार को बताया कि एक 14 वर्षीय लड़की का आंशिक रूप से क्षत-विक्षत शव बाहरी दिल्ली के नरेला इलाके की एक दुकान के अंदर मिला।

लड़की का नौ दिन पहले अपहरण कर लिया गया था और उसका गला घोंटने से पहले कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार किया गया था। उन्होंने बताया कि इस मामले में एक व्यक्ति को सोमवार तड़के गिरफ्तार किया गया जबकि दूसरा फरार है। दिल्ली पुलिस एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि दुकान में काम करने वाले एक मजदूर को सन्नोथ गांव से गिरफ्तार किया गया। वह दिल्ली से मुंबई भागने की कोशिश कर रहा था इसी दौरान पुलिस ने उसे धर दबोचा। उन्होंने कहा कि अपराध में शामिल दूसरे व्यक्ति को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि किशोरी का 12 फरवरी को अपहरण हुआ था और तीन दिन बाद अज्ञात लोगों के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज किया गया था। पुलिस उपायुक्त (आउटर नॉर्थ) बृजेंद्र कुमार यादव ने बताया कि किशोरी के लापता होने के एक हफ्ते बाद पुलिस को दुकान से दुर्गंध आने के बारे में एक दुकानदार का फोन आया। दुकानदार ने कहा कि उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले का एक मजदूर, जिसे वह काम पर रखता था, अनुपस्थित था। पुलिस ने जब दुकान की तलाशी ली तो उसमें लापता किशोरी का शव आंशिक रूप से क्षत-विक्षत पाया गया। उन्होंने कहा कि बोरी दुकान के एक कोने में गाय के गोबर के ढेर के नीचे मिली थी। पुलिस उपायुक्त ने आगे बताया कि पुलिस ने तकनीकी निगरानी और सूत्रों का उपयोग करते हुए पहले आरोपी को पकड़ लिया जिससे पूछताछ में पता चला कि उसने और उसके साथी ने मेट्रो विहार में शराब पी थी और फिर काम के बहाने उसे फोन किया। उन लोगों ने लड़की को धोखे से बुलाया और एक-एक करके उसके साथ बलात्कार किया और फिर उसका गला घोंट दिया।

उन्होंने बताया कि फरार आरोपित की गिरफ्तारी के लिए आगे की कार्रवाई की जा रही है। हम उसके संभावित ज्ञात स्थानों और हरदोई जिले में भी छापेमारी कर रहे हैं। डीसीपी ने कहा कि उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं, बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए बीजेआरएम अस्पताल जहांगीरपुरी की मोर्चरी में रखवाया गया है।

केसीआर, उद्धव और पवार की मुलाकात पर बीजेपी ने ली चुटकी, कहा- गैर कांग्रेस गठबंधन बनाने की हो रही कोशिश

नई दिल्ली।

भारतीय जनता पार्टी ने सोमवार को तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव (केसीआर) के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के प्रमुख शरद पवार से मुलाकात पर चुटकी ली। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने चुटकी लेते हुए कहा कि यह सब राष्ट्रीय स्तर पर एक गैर-कांग्रेसी गठबंधन बनाने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की हालत दिन भर दिन खस्ता हो रही है। बीजेपी प्रवक्ता ने तंज कसते हुए कहा कि जिनके पास देश के लिए कोई विजन और मिशन नहीं है वे प्रधानमंत्री बनने की ख्वाहिश रख रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि 2024 में भारत का पीएम कौन बनना चाहता है, ममता बनर्जी, राव या राहुल गांधी? भाजपा नेता ने कहा कि महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार में कांग्रेस की हालत खराब हो गई है। उन्होंने कहा कि पूरे देश में गैर-कांग्रेसी गठबंधन बनाने के लिए शरद पवार और उद्धव ठाकरे तेलंगाना के मुख्यमंत्री से मिले हैं। पूनावाला ने कहा कि ऐसा लगता है कि बैठक में कांग्रेस के खिलाफ

भाजपा नेता ने कहा कि महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार में कांग्रेस की हालत खराब हो गई है। उन्होंने कहा कि पूरे देश में गैर-कांग्रेसी गठबंधन बनाने के लिए शरद पवार और उद्धव ठाकरे तेलंगाना के मुख्यमंत्री से मिले हैं।

अविश्वास प्रस्ताव पारित किया गया। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में शिवसेना, राकांपा और कांग्रेस गठबंधन में हैं। यह बैठक तब हुई जब तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने विपक्षी दलों को भाजपा के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया। गौरतलब है कि शिवसेना ने मुखपत्र सामना के जरिए रविवार को कहा कि इस बैठक से भाजपा के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक एकता की प्रक्रिया तेज होगी। वहीं तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने इससे पहले भाजपा पर निशाना साधा था और कहा था कि इसे देश से निष्कासित कर देना चाहिए नहीं तो देश बर्बाद हो जाएगा। उन्होंने भाजपा को सत्ता से बाहर करने के लिए राजनीतिक ताकतों को एक साथ आने का भी आह्वान किया था। बता दें कि भाजपा के खिलाफ विभिन्न विपक्षी दलों को एक साथ लाने के प्रयासों के तहत मुख्यमंत्री केसीआर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मिलने की भी योजना बना रहे हैं।

पीएम मोदी बोले- डिजिटल यूनिवर्सिटी भविष्य के लिए फायदेमंद, बजट में शिक्षा व्यवस्था पर जोर

नई दिल्ली । शिक्षा मंत्रालय के एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया कि उनकी सरकार क्वालिटी एजुकेशन को बढ़ावा दे रही है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि ई-विद्या हो, वन क्लास वन चैनल हो, डिजिटल लैब्स हों, डिजिटल यूनिवर्सिटी हो, ऐसा एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर युवाओं को बहुत मदद करने वाला है। नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी, भारत की शिक्षा व्यवस्था में अपनी तरह का अनोखा और अभूतपूर्व कदम है। उन्होंने कहा कि डिजिटल कनेक्टिविटी ही है जिसने वैश्विक महामारी के इस समय में हमारी शिक्षा व्यवस्था को बचाए रखा। हम देख रहे हैं कि कैसे भारत में तेजी से डिजिटल डिवाइड कम हो रहा है। इनोवेशन हमारे यहां inclusion सुनिश्चित कर रहा है। केंद्रीय बजट का सकारात्मक प्रभाव पर चर्चा करते हुए मोदी ने कहा कि आज

की युवा पीढ़ी देश के भविष्य की कर्णधार है और भविष्य के राष्ट्र निर्माता भी हैं। आज की युवा पीढ़ी को सशक्त करने का मतलब है भारत के भविष्य को सशक्त करना है। इसी सोच के साथ 2022 के बजट में शिक्षा क्षेत्र में 5 बातों पर ज़ोर दिया गया है। पहला है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ क्वालिटी एजुकेशन से हमारी शिक्षा व्यवस्था का विस्तार हो, उसकी क्वालिटी सुधरे और एजुकेशन सेक्टर की क्षमता बढ़े, इसके लिए अहम निर्णय लिए गए हैं। दूसरा स्किल डेवलपमेंट है जिससे देश में डिजिटल स्किलिंग इकोसिस्टम बने। तीसरा महत्वपूर्ण पक्ष है- अर्बन और डिज़ाइन जिससे भारत का जो पुरातन अनुभव और ज्ञान है, उसे हमारी आज की शिक्षा में समाहित किया जाए। चौथा अहम पक्ष है अंतर्राष्ट्रीयकरण जिससे भारत में वर्ल्ड क्लास विदेशी यूनिवर्सिटियां आएं। पांचवा पक्ष बताते हुए मोदी ने कहा कि पांचवा महत्वपूर्ण पक्ष है- AVGC- यानि एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स इन सभी में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं और एक बहुत बड़ा ग्लोबल मार्केट है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बजट में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास बहुत आवश्यक है। बजट सिर्फ आंकड़ों का लेखा-जोखा नहीं है। बजट हम सही ढंग से सही समय पर सही तरीके से उपयोग करें तो हमारे सीमित संसाधनों से भी हम बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। डिजिटल यूनिवर्सिटी में वो ताकत देख सकता हूं कि ये यूनिवर्सिटी हमारे देश में सीटों की समस्या को पूरी तरह से समाप्त कर सकती है।

नर्सरी एडमिशन की दूसरी लिस्ट जारी

नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में नर्सरी दाखिला के लिए परेशान लोगों के लिए बड़ी खबर है। दिल्ली में नर्सरी दाखिले की प्रक्रिया के तहत सोमवार को दूसरी मेरिट लिस्ट जारी हो गई है। ऐसे में उन अभिभावकों की नजर सोमवार की लिस्ट पर है, जिन बच्चों का नाम पहली सूची में नहीं आया था। दूसरी लिस्ट में नाम आया या नहीं, इसकी जानकारी शिक्षा निदेशालय की आधिकारिक साइट edudel.nic.in पर ले सकते हैं। बता दें कि दिल्ली नर्सरी दाखिले की पहली सूची को 4 फरवरी को जारी कई गई थी, जिसके तहत दाखिला प्रक्रिया 12 फरवरी तक चली थी। इसके बाद सोवार को बची हुई सीटों के लिए स्कूलों द्वारा दूसरी सूची जारी की जाएगी। नर्सरी दाखिले के लिए सोमवार को दूसरी सूची जारी होने के बाद इसके तहत आगामी 22 फरवरी यानी मंगलवार से लेकर 28 फरवरी तक दाखिले की प्रक्रिया चलेगी। पहली सूची के तहत चयनित छात्रों की दाखिला प्रक्रिया पूरी करने के बाद भी स्कूलों में 25 से 30 प्रतिशत सीटें खाली रह गई हैं। इसके लिए स्कूलों द्वारा सोमवार को दूसरी सूची जारी की गई है। अपने बच्चों को नाम लिस्ट में देखने के लिए शिक्षा निदेशालय की आधिकारिक साइट edudel.nic.in पर जाना होगा। इसका एक विकल्प यह भी है कि आप संबंधित स्कूलों की वेबसाइट पर भी यह जानकारी देख सकते हैं। लिस्ट देखने की कड़ी में सबसे पहले होम पेज पर उपलब्ध एडमिशन लिंक पर क्लिक करना होगा। इसके बाद एक नया पेज खुल जाएगा, जहां योग्य उम्मीदवार उपलब्ध नर्सरी, केजी और प्रथम दूसरी सूची लिंक पर क्लिक करना होगा। इसके बाद वार्ड का नाम चेक करें और फिर पेज डाउनलोड कर लें। गौरतलब है कि नर्सरी के साथ-साथ केजी और प्रथम कक्षा में दाखिले की प्रक्रिया जारी है और इस प्रक्रिया के जरिए 1,800 से अधिक स्कूलों में नर्सरी दाखिले किए जाने हैं। नियमानुसार, दूसरी सूची जारी होने के बाद भी अगर स्कूलों में सीटें बच जाती हैं, तो तीसरी सूची जारी होगी। तीसरी मेरिट लिस्ट के लिए 16 मार्च से एडमिशन शुरू होंगे, जबकि 31 मार्च तक नर्सरी एडमिशन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

30 लाख मेट्रो यात्रियों को कब मिलेगी खुशखबरी, दिल्ली सरकार की पहल का इंतजार

नई दिल्ली। कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में कमी आने के बाद दिल्ली-एनसीआर के इलाकों में आइटी सेक्टर को छोड़कर तकरीबन दफ्तरों में सुचारु रूप से काम होने लगा है। लोग अब रोजाना दफ्तरों में काम के लिए जाने लगे हैं। ऐसे में सबसे बड़ी दिक्कत आवाजाही में हो रही है। दिल्ली-एनसीआर की लाइफलाइन कही जाने वाली दिल्ली मेट्रो का परिचालन सामान्य रूप से नहीं होने से लोगों को अधिक दिक्कत हो रही है। मेट्रो यात्रियों को कहना है कि दिल्ली सरकार को पहल कर दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक बुलाई जानी चाहिए, जिसमें दिल्ली मेट्रो को पूरी क्षमता के साथ संचालित करने का निर्णय हो। पीक आवर में दिल्ली मेट्रो में जबरदस्त भीड़ होने लगी है। सुबह और शाम को भीड़ इस कदर बढ़ जाती है कि कोरोना प्रोटोकाल भी कायम नहीं रह पाता है। कहा जा रहा है कि दिल्ली और एनसीआर के शहरों में सभी तरह के दफ्तरों के खुलने के बाद फिलहाल प्रतिदिन करीब करीब 15 लाख यात्री सफर कर रहे हैं। ऐसे

में सुबह और शाम को मेट्रो में जबरदस्त भीड़ होने लगी है। पीक आवर में यात्रियों की भारी संख्या के चलते मेट्रो प्रशासन को भी दिक्कत आ रही है। दरअसल. कोविड-19 की स्थिति में सुधार तो हुआ है, लेकिन दिल्ली मेट्रो फिलहाल पूर्ण क्षमता के साथ नहीं दौड़ रही है। फिलहाल सभी सीटों पर बैठकर लोग यात्रा कर सकते हैं, लेकिन खड़े होकर यात्रा करने पर अब भी पाबंदी है। ऐसे में लोगों को दिक्कत आ रही है। लोगों को अपना सफर तय करने में अधिक समय लग रहा है।

सूत्रों ने पूर्व में बताया था कि प्रत्येक डिब्बे में 50 लोग ही यात्रा कर सकते हैं। इससे पहले एक डिब्बे में 300 लोग यात्रा करते थे, 50 सीट पर बैठकर और 250 लोग खड़े होकर यात्रा करते थे। डीएमआरसी ने लोगों से आवश्यक होने पर ही यात्रा करने की अपील की है. डीएमआरसी के तहत 10 लाइन में 242 स्टेशन हैं और गुड़गांव में रैपिड मेट्रो सहित कुल 264 स्टेशन हैं। मेट्रो सेवाएं आमतौर पर 5:30 बजे से शाम 11:30 बजे शुरू होती हैं। कोरोना से अलग अगर दिल्ली मेट्रो के समय की बात करें तो, मेट्रो ट्रैन अपने अधिकतर रूटों पर सुबह 5 बजकर 45 मिनिट पर शुरू हो जाती है। मेट्रो रेल में उड़न दस्तों को कोविड-19 नियमों का अनुपालन कराने के लिए तैनात किया गया है, कोरोना प्रोटोकाल का उल्लंघन करने वालों पर 200 रुपये का जुर्माना करते हैं।

पद्मश्री से सम्मानित 102 वर्षीय गांधीवादी शकुंतला चौधरी का निधन, प्रधानमंत्री मोदी से जताया शोक

नई दिल्ली ।

पद्मश्री से सम्मानित 102 वर्षीय गांधीवादी शकुंतला चौधरी का निधन हो गया है। गुवाहाटी के सरानिया आश्रम में उनकी देखभाल करने वाले लोगों ने बताया कि उनका पिछले 10 वर्षों से इलाज चल रहा था और रविवार रात को उम्र संबंधी बीमारियों के कारण उनका निधन हो गया। वह दशकों से इसी आश्रम में रह रही थीं। उन्होंने बताया कि उनका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए आश्रम में रखा गया है और उनका अंतिम संस्कार सोमवार को नबगृह शवदाहगृह में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक जताया और कहा कि गांधीवादी मूल्यों में दृढ़ विश्वास रखने के लिए उन्हें याद किया जाएगा। उन्होंने ट्वीट किया, शकुंतला चौधरी जी को गांधीवादी मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए उनके जीवनभर के प्रयासों के लिए याद किया जाएगा। सरानिया आश्रम में उनके नेक काम ने कई लोगों की जिंदगियों पर सकारात्मक असर डाला। उनके निधन से दुखी हूं। उनके परिवार तथा असंख्य

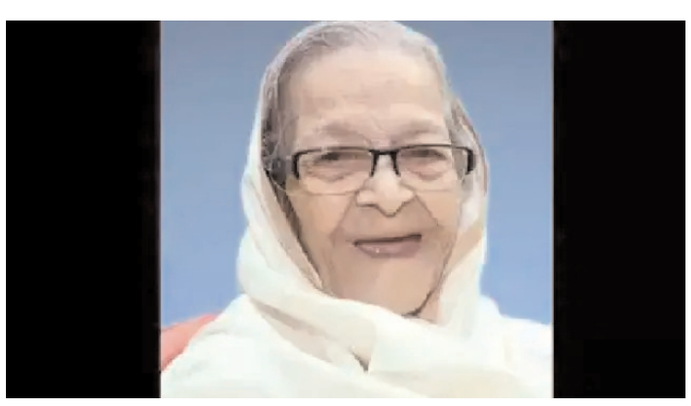

प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। ओम शांति। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने भी उनके निधन पर शोक जताते हुए ट्वीट किया, गांधीवादी और पद्म श्री शकुंतला चौधरी के निधन से बहुत दुखी हूं। उनका जीवन सरानिया आश्रम, गुवाहाटी में निस्वार्थ सेवा, सच्चाई, सादगी और अहिंसा के प्रति समर्पित रहा, जहां महात्मा गांधी 1946 में रहे थे। उनकी सद्गति की प्रार्थना करता हूं। ओम शांति।

राज्य के मंत्रियों केशब महंत और रानोज पेगू ने सरानिया आश्रम में सरकार की ओर से चौधरी के पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित की। गुवाहाटी में जन्मी शकुंतला पढ़ाई में काफी अच्छी थीं और गुवाहाटी के टीसी स्कूल में अध्यापन के दौरान ही वह अन्य गांधीवादी अमलप्रोवा दास के संपर्क में आयी, जिनके पिता ने सरानिया हिल्स की अपनी संपत्ति आश्रम बनाने के लिए दान में दे दी थी। दास ने चौधरी से ग्राम सेविका विद्यालय चलाने और कस्तूरबा गांधी नेशनल मेमोरियल ट्रस्ट (केजीएनएमटी) की असम शाखा के प्रबंधन में मदद करने का अनुरोध किया था। इसके बाद वह कार्यालय सचिव बन गयी और उन्हें ट्रस्ट के प्रशासन का जिम्मा दिया गया। इसके साथ ही वह विद्यालय में पढ़ाती भी रहीं। चौधरी ने 1955 में केजीएनएमटी के प्रतिनिधि का पद संभाला और 20 वर्षों तक चीनी आक्रमण, तिब्बती शरणार्थी संकट, 1960 के भाषायी आंदोलन जैसे कई घटनाक्रम के बीच मिशन का नेतृत्व किया। अपने जीवन में वह विनोबा भावे से भी जुड़ी रहीं और उनके मशहूर भूदान आंदोलन के अंतिम चरण के दौरान असम में डेढ़ साल तक चली पदयात्रा में भी शामिल हुईं।

सम्पादकीय

योगक्षेमं वहाम्यहम् की परख

योगक्षेमं वहाम्यहम् यह जीवन बीमा निगम का सूत्र वाक्य है। आज भी एलआईसी के 'लोगो' के नीचे आप गीता के एक श्लोक का यह हिस्सा लिखा हुआ पा सकते हैं। कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया, उसके नौवें अध्याय में से यह छोटा सा हिस्सा जिसने भी जीवन बीमा निगम के लिए चुना, उसकी तारीफ करनी चाहिए। इसका अर्थ है कि मैं आपकी पूरी कुशलता का बोझ धारण करूंगा, यानी आपकी पूरी चिंता का बोझ मैं उठा लूंगा। जो आपके पास है, उसकी रक्षा करूंगा और जो नहीं है, वह आपको दिलवाऊंगा। जीवन बीमा का काम इसके अलावा और क्या है? 1956 में देश में बीमा कारोबार का राष्ट्रीयकरण हुआ और जीवन बीमा का पूरा कारोबार समेटकर एलआईसी के हवाले कर दिया गया। तभी से भारत में जीवन बीमा का मतलब एलआईसी ही होता रहा है। बहुत से लोग बोलचाल में कहते भी हैं, एलआईसी करवा लिया, मतलब बीमा करवा लिया। लेकिन इस वक्त एलआईसी का मतलब शेयर बाजार व सरकार के लिए कुछ और ही है और शेयर बाजार से जुड़े या जुड़ने की इच्छा रखने वाले लोगों के लिए भी। फिर भले ही नए निवेशक हों या वर्षों से शेयर बाजार में जमे पुराने खिलाड़ी। सब देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी एलआईसी, यानी भारतीय जीवन बीमा निगम के आईपीओ के इंतजार में हैं। एलआईसी देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी होने के साथ ही, देश के सबसे बड़े जमींदारों में से एक है। देश के हर बड़े-छोटे शहर में इसके पास संपत्ति है। पैसा भी इतना है कि यह शेयर बाजार को चढ़ाने और गिराने का दम रखती है। जेफरीज ने कुछ समय पहले एक शोध पत्र निकाला था, जिसके हिसाब से लिस्टिंग के बाद एलआईसी की कुल हैसियत 261 अरब डॉलर के करीब हो सकती है। सरकार कह चुकी है कि वह इसका पांच से दस प्रतिशत हिस्सा बेचने के लिए आईपीओ ला सकती है। दस प्रतिशत भी बिका, तो वह 26 अरब डॉलर, यानी करीब 1.92 लाख करोड़ रुपये का इशू होगा। हालांकि, यह बात साफ है कि सरकार एक बार में एलआईसी का पांच प्रतिशत से ज्यादा हिस्सा नहीं बेच पाएगी। पांच प्रतिशत का मतलब है कि सरकार एलआईसी के 31.72 करोड़ तक शेयर बाजार में बेचने के लिए उतारेगी। इन शेयरों का भाव क्या रखा जाता है, इससे तय होगा कि सरकार को इससे कितना पैसा मिलेगा। लेकिन अनुमान है कि यह रकम पचास हजार करोड़ से एक लाख करोड़ रुपये तक हो सकती है। यह भारत के शेयर बाजार के इतिहास का सबसे बड़ा आईपीओ होगा। सरकार के लिए यह आईपीओ या एलआईसी का विनिवेश बहुत जरूरी भी है, क्योंकि उसने सरकारी कंपनियों में हिस्सेदारी बेचकर पौने दो लाख करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा है। इस साल का लक्ष्य 78 हजार करोड़ रुपये बचा हुआ है, और सिर्फ एलआईसी की पांच प्रतिशत हिस्सेदारी उसका यह लक्ष्य पार करवा सकती है।

यहां यह ध्यान रखना जरूरी है कि एलआईसी कोई नए शेयर जारी नहीं कर रही है। सरकार इसमें अपनी हिस्सेदारी यानी अपने हिस्से के शेयरों में से ही कुछ भाग बेच रही है। इससे एलआईसी की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यह पूरी रकम सरकार के खजाने में जाएगी। एलआईसी को इसमें से एक पैसा नहीं मिलनेवाला है। उसको पैसे की जरूरत है भी नहीं। देश के जीवन बीमा कारोबार की दो तिहाई हिस्सेदारी है उसके पास। 2020 में उसके पास प्रीमियम के रास्ते 5,640 करोड़ डॉलर की रकम आई थी, और इस पैमाने पर वह दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी है। 2021 में उसे मिला प्रीमियम 4032.9 अरब रुपये है। आईपीओ के बाद कंपनी की सेहत पर यह फर्क जरूर पड़ेगा कि अभी तक वह सिर्फ सरकार के प्रति जवाबदेह थी, जबकि इसके बाद उसे हर तीन महीने पर अपने शेयरहोल्डरों को हिसाब देना पड़ेगा, मतलब प्रबंधन को पारदर्शी बनाना पड़ेगा। उम्मीद है, लिस्टिंग के साथ ही एलआईसी मॉर्गन स्टैनली के एमएससीआई इंडेक्स में शामिल हो सकती है, यानी विदेशी निवेशकों के लिए यह एक आकर्षक शेयर होगा। विदेशी निवेशकों को कंपनी की तरफ आकृष्ट करने के लिए कानूनी बदलाव की भी जरूरत है। आईपीओ में पांच प्रतिशत हिस्सा एलआईसी के कर्मचारियों के लिए अलग रखा जा सकता है। खबर है कि पहली बार एलआईसी अपने बीमाधारकों के लिए भी एक अलग कोटा रखने की तैयारी कर रही है। एलआईसी के पास करीब 29 करोड़ बीमाधारक हैं और पिछले काफी समय से एलआईसी एजेंट उन्हें समझा रहे हैं कि कैसे अपनी पॉलिसी को आधार से लिंक करवाना है और कैसे डीमैट अकाउंट खोलकर आईपीओ के पहले ही तैयारी पूरी कर लेनी है। अगर इनमें से आधे या चौथाई लोग भी शेयर के लिए अर्जी लगा देते हैं, तो एक बड़ी बिरादरी बन जाएगी। पूरी उम्मीद है कि आईपीओ में जो भी भाव तय होगा, इन दोनों वर्ग के लोगों को कुछ रियायत भी दी जाएगी। बीमाधारकों को कोटा मिलने का मतलब यह कतई नहीं है कि उन्हें मुफ्त में शेयर मिलनेवाले हैं। यह देश का सबसे बड़ा आईपीओ है, इसलिए इसके साथ बहुत-सी आशंकाएं भी खड़ी हो रही हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या बाजार का माहौल इस वक्त एक साथ इतनी बड़ी रकम जुटाने के लिए ठीक है। कहीं ऐसा न हो कि पेटीएम की तरह एलआईसी का भाव भी कुछ ऐसा हो कि बाजार में उत्साह बढ़ाने की जगह उस पर पानी फिर जाए। इसलिए इस बात का दारोमदार बहुत हद तक इस पर है कि सरकार एलआईसी के शेयर किस भाव पर बेचने को तैयार होती है। अगर दाम ऊंचा रखा गया, तो फिर यह न सिर्फ एलआईसी के लिए, बल्कि बाजार के लिए भी बुरी खबर साबित हो सकती है। वैसे पूरी संभावना है कि एलआईसी के आईपीओ के साथ बाजार में तेजी की एक नई लहर दौड़ सकती है। करोड़ों नए डीमैट अकाउंट खुलेंगे और बाजार में बड़ी संख्या में नए निवेशक आएंगे।

हिजाब विवाद : सिर्फ औरतें चेहरा क्यों छिपाएँ?

कर्नाटक के उच्च न्यायालय में हिजाब के मुद्दे पर अभी बहस जारी है लेकिन अंतरराष्ट्रीय इस्लामी सहयोग संगठन (ओआईसी) ने भारत के खिलाफ अपना बयान जारी कर दिया है। उसने पहले धारा 370 हटाने के विरोध में भी बयान जारी किया था। पाकिस्तान के मुल्ला-मौलवी और नेता भी एकतरफा बयान जारी करने में एक-दूसरे से आगे निकल रहे हैं। कर्नाटक की अदालत में हिजाब का पक्ष रखनेवाले वकील हिंदू हैं और वे जो तर्क दे रहे हैं, वे ऐसे हैं, जिन पर खुले दिमाग से विचार किया जाना चाहिए। उनका तर्क यह है कि जब हिंदू औरत के सिंदूर, बिंदी और चूड़ियों, सिखों की दाढ़ी-मूंछ और पगड़ी तथा ईसाइयों के क्रॉस पहनने पर कोई प्रतिबंध नहीं है तो मुस्लिम महिलाओं के बुर्के और हिजाब पर प्रतिबंध की क्या तुक है? क्या ऐसा करना पूर्णतः सांप्रदायिक कदम नहीं है? क्या यह इस्लाम और मुसलमानों पर सीधा आक्रमण नहीं है? हिजाब के बहाने यह मुस्लिम लड़कियों को शिक्षा से वंचित करने का कुप्रयास नहीं है? ये तर्क बहुत वाजिब दिखाई पड़ते हैं लेकिन अभी कर्नाटक में हिजाब के सवाल ने जैसा सांप्रदायिक और राजनीतिक रुप धारण कर लिया है, यदि हम उससे ज़रा अलग हटकर सोचें तो यह मूलतः नर-नारी समता का सवाल है! यदि हिजाब धार्मिक चिन्ह है तो इसे औरतों के साथ-साथ मर्द भी क्यों नहीं पहनते? आजकल औरत और मर्द- सभी मुखपट्टी (मास्क) पहनते हैं, वैसे ही वे हिजाब भी पहन सकते हैं। सिर्फ औरतें ही क्यों हिजाब पहनें? उनका गुनाह क्या है? और फिर मुस्लिम औरतों को ही यह सजा क्यों है ? हिंदू और ईसाई औरतें भी इसे क्यों नहीं पहनें? हिजाब, बुर्का, घूंघट, सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, भगवान दुपट्टा आदि इनमें से किसी भी चीज को पहनने का आदेश किसी ईश्वर, अल्लाह या अहुरमज्द का नहीं है। ये सब परंपराएं मुनष्यों की बनाई हुई हैं और ये देश-काल के मुताबिक चलती हैं। हिजाब और बुर्के का औचित्य डेढ़ हजार साल पुराने अरब देश में बिल्कुल ठीक था लेकिन आज की दुनिया में इसका कोई महत्व नहीं रह गया है। यदि हिजाब और बुर्का इस्लाम का अनिवार्य अंग है तो क्या बेनज़ीर भुट्टो, मरियम नवाज शरीफ, शेख हसीना, काबुल की शहजादियां मुसलमान नहीं हैं? मैंने तो उन्हें कभी भी अपना चेहरा छिपाते हुए नहीं देखा! शरीर के गुप्तांग औरत और मर्द सभी ढकें, यह तो जरुरी है लेकिन चेहरे को छिपाए रखने की पीछे तर्क क्या है? चेहरा तो आपकी पहचान है। चेहरा तो वो ही छिपाता फिरता है, जो चोर, डाकू, तस्कर या अपराधी हो। किसी तिलक, बिंदी, चोटी, जनेऊ, दाढ़ी-मूंछ, पगड़ी, दुपट्टा, तुर्की टोपी, शेरवानी, सलवार-कमीज, गतरा (अरब), चोंगा (ईसाई), किप्पा (यहूदी टोपी) आप पहनना चाहें तो जरुर पहनें। आप अपनी मजहबी या सांप्रदायिक या जातीय पहचान का दिखावा करना चाहते हैं तो जरुर करें। लेकिन कोई भी औरत या मर्द अपना मुंह क्यों छिपाए? मुखपट्टी तो जैन मुनि भी लगाते हैं लेकिन उसका उद्देश्य अपना मुंह या पहचान छिपाना नहीं है बल्कि उनकी गर्म सांस से कोई जीव-हिंसा न हो जाए, उनका यह उद्देश्य रहता है। औरतों पर हिजाब, नकाब और बुर्का लादना तो उनकी हैसियत को नीचे गिराना है। मुस्लिम कन्याओ को छात्र-काल से ही हीनता-ग्रंथि से ग्रस्त कर देना कहां तक ठीक है? मुस्लिम कन्याओं का मनोबल भी उतना ही ऊंचा रहना चाहिए, जितना देश की अन्य लड़कियों का रहता है।

लोकतंत्र को मजबूत करने के नाम पर परिवारवाद को पोषित करने में लगे क्षेत्रीय दल

राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष को एकजुट करने की पहल कोई नई-अनोखी बात नहीं। यह काम रह-रहकर होता ही रहता है। कुछ समय पहले ममता बनर्जी इसके लिए तेजी से सक्रिय हुईं, लेकिन जब उन्होंने कांग्रेस के बगैर विपक्ष दलों को जोड़ने के इरादे से मुंबई का दौरा किया तो शिवसेना उनसे दूरी बनाती दिखी। अब तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव विपक्ष को एकजुट करने के अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। गत दिवस उन्होंने मुंबई में उद्धव ठाकरे के अतिरिक्त शरद पवार से भी मुलाकात की। आने वाले दिनों में वह अन्य विपक्षी नेताओं से भी भेंट कर सकते हैं। चंद्रशेखर राव इसके पहले भी विपक्षी एकता के लिए प्रयास कर चुके हैं, लेकिन बाद में वह न केवल भाजपा के करीब आए, बल्कि संसद में कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर मोदी सरकार के साथ खड़े भी हुए। वह पिछले कुछ समय से भाजपा से भड़के हुए हैं और उसे खरी-खोटी सुनाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। ऐसा लगता है कि हैदराबाद नगर निगम चुनावों के साथ एक विधानसभा सीट के लिए हुए उपचुनाव में भाजपा की जीत ने उनकी चिंता बढ़ा दी है। वह पिछले दिनों तेलंगाना गए प्रधानमंत्री की अगवानी करने भी नहीं पहुंचे। भाजपा से उनकी नाराजगी का कारण कुछ भी हो, इससे इन्कार नहीं कि देश को एक सबल विपक्ष चाहिए। लोकतंत्र के भले के लिए विपक्ष का सशक्त होना आवश्यक है, लेकिन समस्या यह है कि भाजपा का विकल्प तैयार करने की कोशिश करने वाला विपक्ष का हर नेता विपक्षी एका की कमान अपने हाथ में रखना चाहता है। इससे भी बड़ी समस्या यह है कि वे विकल्प तैयार करने की बातें तो खूब करते हैं, लेकिन देश के सामने कोई ठोस एजेंडा और स्पष्ट नजरिया प्रस्तुत नहीं कर पाते। इसका एक बड़ा कारण राष्ट्रीय महत्व के विषयों की तुलना में क्षेत्रीय मसलों को कहीं अधिक प्राथमिकता देना है। विपक्षी दल यह समझें तो बेहतर कि कोई ठोस विकल्प तभी बन सकता है, जब वे राष्ट्रीय दृष्टि से लैस हों। यह विचित्र है कि वे संघीय ढांचे को मजबूत करने की जरूरत तो जताते हैं, लेकिन प्रायः उसके ही खिलाफ काम करते हैं। कई बार तो वे विकास और सामाजिक कल्याण की केंद्रीय योजनाओं को लागू करने में नकारात्मक रवैये का प्रदर्शन भी करते हैं।

यूपी-बिहार के भइयों के दिल में भी बसता है पंजाब

पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने राजनीतिक अपेक्षा से बिहार-यूपी के मेहनतकश लोगों के लिए जो भी कहा, वह अब उन्हीं की पार्टी पर उल्टा पड़ता दिख रहा है। झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश में बसे पंजाबियों को प्रियंका वाड्रा की मौजूदगी में चन्नी का उद्गार बहुत नागवार गुजरा है। चन्नी को शायद नहीं पता कि एक पंजाब उन प्रदेशों में भी बसता है, जहां के प्रवासियों को वह भइया और बाहरी कहते-समझते हैं। यह सच है कि उत्तर-पूर्वी भारत के लाखों लोग पंजाब में आजीविका चला रहे हैं तो यह भी झूठ नहीं है कि पंजाबियों की बड़ी आबादी देश के दूसरे प्रदेशों में भी निवास करती है और रोजी-रोटी कमाती है। इससे संबंधित केंद्र सरकार का एक आंकड़ा है, जो चरणजीत सिंह चन्नी के साथ ही पूर्वांचल के राज्यों में राजनीति करने वाले दलों के कर्णधारों की भी आंखें खोल सकती हैं। कोरोना काल में लाकडाउन के दौरान विभिन्न प्रदेशों से अभी तक घर लौटने वाले लोगों (या कामगारों) की संख्या एक करोड़ 14 लाख 30 हजार 968 है। इनमें से यूपी के 32 लाख 49 हजार और बिहार के 15 लाख लोग हैं तो पंजाब के भी पांच लाख 15 हजार लोग हैं। विस्थापन का समय और तरीका बताता है कि ये सारे कामगार रहे होंगे, जो विवशता में घर-बार छोड़कर दूसरे प्रदेशों में जाते हैं। स्पष्ट है कि लाकडाउन के दौरान असुरक्षा के चलते जब विभिन्न प्रदेशों से लोग बेतहाशा अपने गांव की ओर लौट रहे थे तो दूसरे प्रदेशों में रहने वाले लाखों पंजाबियों की भी घर वापसी हुई थी। इसका मतलब हुआ कि इतनी बड़ी संख्या में पंजाबी भी दशकों से दूसरे प्रदेशों में अपनी आजीविका चला रहे थे। उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड की आबादी को आधार मानकर अगर औसत निकाला जाए तो पंजाब से बाहर जाकर रोजी-रोटी कमाने वाले लोगों की संख्या बिहार की तुलना में थोड़ा ही कम होगी। चन्नी के पंजाब में बाहरी लोगों के राज करने की दलील का अंदाजा एक और आंकड़े से भी लगाया जा सकता है, जो यह बताता है कि पंजाब से बाहर भी एक मुकम्मल पंजाब बसता है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में 71 हजार 422 एवं बिहार में 23 हजार 779 लोग सिख समुदाय के हैं, जबकि यूपी में सिखों की संख्या छह लाख 44 हजार से भी ज्यादा है। निश्चित तौर पर एक दशक के दौरान इस संख्या में वृद्धि ही हुई होगी। धर्म के हिसाब से उत्तर प्रदेश में हिंदू और मुस्लिम के बाद तीसरी बड़ी आबादी सिखों की है। झारखंड में इनकी पांचवीं बड़ी आबादी है। यह संख्या सिर्फ सिख समुदाय के लोगों की है। पंजाब के अन्य समुदाय के लोगों को अगर जोड़ दिया जाए तो यह दोगुनी-तिगुनी भी हो सकती है। यूपी-बिहार के भइयों के बारे में कुछ भी बोलने से पहले चन्नी अगर अपनी सरकार से इन आंकड़ों पर बात कर लेते तो शायद बोलने से परहेज करते। साथ ही यूपी और बिहार में सहयोगी दलों से अलग होकर अपने दम पर सियासी जमीन की तलाश कर रही कांग्रेस के लिए भी मुसीबत नहीं खड़ा करते। पूर्वोत्तर भारत के मेहनतकशों का अनादर करने से पहले चन्नी को पता कर लेना चाहिए था कि पंजाब का बिहार से किस तरह का सनातन रिश्ता है। सिखों के दसवें गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्म ही पटना में हुआ था। तख्त श्री पटना साहिब में 22 दिसंबर 1666 को वह प्रकट हुए थे। उनके बचपन के चार वर्ष पटना में ही बीते थे। उसके बाद ही वह पिता तेगबहादुर के साथ पंजाब लौट सके थे। इसके पहले भी राजगीर, गया और नवादा में गुरु नानक देव के चमत्कारों की कई सारी स्मृतियां हैं। पटना साहिब में महज पांच वर्ष पहले 350वें प्रकाश पर्व के आयोजन की भव्यता भी यदि चन्नी की स्मृति में होती तो वह अपने गुरु की जन्मभूमि के लोगों को सम्मान की नजरों से देखते और अपने प्रदेश की अच्छी अर्थव्यवस्था के लिए अहसान मानते। बाहरी आक्रांताओं से भारतीयता की रक्षा के लिए हिंदुओं और सिखों ने संयुक्त संघर्ष किया है। दोनों का इतिहास अलग नहीं रहा है। मिलकर मुकाबला किया। चन्नी ने यूपी-बिहार के भइयों' के बारे में बोलकर पंजाबियत सभ्याचार का नुकसान किया है। शायद उन्हें यह भी नहीं पता है कि आजादी के बाद पंजाब के लोग बड़ी संख्या में यूपी-बिहार के शहरों में बस गए थे। अब ऐसे घुलमिल गए हैं कि पंजाबियों को अलग करके देखा ही नहीं जा सकता है। गांवों में भी बसने लगे हैं। आजादी से पहले भी पंजाबियत का पूरे देश से सनातन रिश्ता रहा है। बिहार में कभी वे पराया नहीं समझे गए। दशम गुरु के समय से ही बिहार के गांवों में छिटपुट रूप से एक अच्छी परंपरा चली आ रही है। चन्नी को इसके बारे में भी जानना चाहिए। कई परिवारों के बड़े बेटे सदियों से खालसा की सेवा में समर्पित होते आ रहे हैं। इसी परंपरा के तहत पटना जिले के एनखां गांव के जमींदार परिवार के एक युवक राघवेंद्रधारी सिंह ने करीब आठ दशक पहले सिख धर्म अपना लिया था। गुरु का अमृत छक कर पगड़ी को अपनी पहचान बना ली थी। पटना गुरुद्वारा साहिब के प्रधान भी बनाए गए। सरदार मौलेश्वर सिंह गुरुद्वारा के सचिव और नौबतपुर रामपुर के सरदार रंगनाथ सिंह प्रचारक बनाए गए थे। वाहे गुरु की सेवा में जाने वाले सरदार राघवेंद्र धारी सिंह अकेले नहीं थे।

उनके साथ करीब डेढ़ हजार युवाओं ने दशम गुरु के रास्ते पर चलना स्वीकार किया। अख्तियारपुर गांव के सरदार कृष्णा सिंह, काब गांव के सरदार लक्ष्मण सिंह एवं सरदार गिरिजेश सिंह सरीखे दर्जनों की पहचान खालसा पंथ से जुड़ गई थी। सरदार कृष्णा सिंह तो अरवल से विधायक भी चुने जाते रहे थे। दक्षिण बिहार के गांवों में यह परंपरा जहां-तहां आज भी कायम है। अरवल जिले के सोनभद्र गांव के निवासी सरदार रणविजय सिंह भूमिहार परिवार से आते हैं, किंतु उनके लिए धर्म का मतलब खालसा है। परिवार के सारे सदस्य हिंदू हैं, लेकिन सरदार रणविजय सिंह स्वयं को सिख कहते हैं। न उन्हें कोई दिक्कत होती है न उनके परिवार को। एक छत के नीचे दोनों पंथ के कार्य होते हैं। चन्नी अगर पंजाब के बाहर पंजाबियत के इस कद्र को समझते तो भइयों को सम्मान के साथ याद करते।

अयोध्या में कम्युनिस्ट.. अरे, क्या कह रहे हैं भाईसाहब!

हम चुनाव इसलिए लड़ रहे हैं ताकि अयोध्या की एकतरफा तस्वीर बदली जा सके। यह नगरी भारतीय धर्मो की प्रतीक स्थली रही है। यहां हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख और इस्लाम सभी धर्मो के स्थल रहे हैं। अयोध्या में पांच जैन तीर्थंकर पैदा हुए। यहां गुरुनानक देव आए। यह गुरद्वारा है। यहां नौगजी बाजार है। यहां इब्राहीम शाह की मजार है। लोग उसे मक्का खुर्द के रूप में मानते हैं।''

अयोध्या में कम्युनिस्ट! यह सुनकर गोदी मीडिया का कोई भी पत्रकार या तो भड़क जाएगा और आपका मुंह नोच लेगा या फिर आपको अज्ञानी साबित करने लगेगा। वैसे यह बात किसी सामान्य व्यक्ति को भी हैरान कर सकती है कि भारतीय दक्षिणपंथ के तूफान का एपीसेंटर (नाभि) बन चुके अयोध्या में वामपंथी कहां से आ गए ? लेकिन यह सच है कि अयोध्या में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के टिकट और हंसिया बाली चुनाव चिह्न पर सूर्यकांत पांडेय चुनाव लड़ रहे हैं ताकि यहां की दूसरी परंपरा जिंदा रहे। वे पिछली बार यानी 2017 में भी लड़े थे लेकिन महज 2,500 वोट पाकर अपनी जमानत गंवा बैठे थे। फिर वे हिंदुत्व की इस राजधानी में कौन सी क्रांति करना चाहते हैं? इस सवाल के उत्तर में वे बताते हैं कि ---

हम लड़ रहे हैं इसलिए कि प्यार जग में जी सके।
आदमी का खून कोई आदमी न पी सके।।

उनका कहना है कि उदार हिंदूवाद कट्टर हिंदूवाद से लड़ नहीं सकता। वह डरा हुआ है। इसलिए वह कभी जनेऊ पहन कर आता है तो कभी मंदिरों के चक्कर काटने लगता है। यह खतरनाक है। ऐसे माहौल में सांप्रदायिक नारे के बगैर कम्युनिस्ट पार्टी लोगों को आने वाले खतरे के प्रति आगाह करना चाहती है। हम चुनाव इसलिए लड़ रहे हैं ताकि अयोध्या की एकतरफा तस्वीर बदली जा सके। यह नगरी भारतीय धर्मों की प्रतीक स्थली रही है। यहां हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख और इस्लाम सभी धर्मों के स्थल रहे हैं। अयोध्या में पांच जैन तीर्थंकर पैदा हुए। यहां गुरुनानक देव आए। यह गुरद्वारा है। यहां नौगजी बाजार है। यहां इब्राहीम शाह की मजार है। लोग उसे मक्का खुर्द के रूप में मानते हैं।'' अयोध्या के राममंदिर बाबरी मस्जिद विवाद के फैसले पर टिप्पणी करते हुए वे कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस बात से शुरू होता है कि ऐसा कोई सबूत नहीं मिलता कि यहां मंदिर गिराकर मस्जिद बनाई गई। दूसरी बात यह कि जिन्होंने मस्जिद गिराई वे दोषी हैं। अगर फैसला रामजन्मभूमि के पक्ष में आता है तो वह रामलला विराजमान के नाते। सुप्रीम कोर्ट रामलला विराजमान के दोस्त के पक्ष में फैसला देता है। उसकी दलील है कि यहां 1949 से पूजा हो रही है इसलिए उसे हटाना गलत है। इसीलिए उसे भूमि देने का निर्णय हुआ है। इतने स्पष्ट फैसले के बावजूद एक पार्टी मुसलमानों को इस फैसले को लेकर निशाने पर क्यों रखती है? वास्तव में आज के अयोध्या और तब के फैजाबाद जिले में कम्युनिस्ट आंदोलन का पुराना इतिहास है। उस इतिहास में कम्युनिस्ट इस इलाके में हमेशा विफल ही नहीं रहे हैं। इस जिले में बाबूजी के नाम से मशहूर मित्रसेन यादव कभी कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े नेता हुआ करते थे। वे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के टिकट पर 1977, 1980 और 1985 में तीन बार विधायक चुने गए थे। एक बार मिल्कीपुर से और दो बार बीकापुर से। इसके अलावा वे 1991 में फैजाबाद जिले से लोकसभा के लिए भी भाकपा के टिकट पर चुने गए। उसके बाद वे वर्ग संघर्ष की राजनीति से डर गए और जाति की राजनीति करने वाले दलों में आते जाते रहे। जिसके कारण वे एक बार समाजवादी पार्टी और एक बार बहुजन समाज पार्टी से लोकसभा के लिए चुने गए। लेकिन जनपद में कम्युनिस्ट पार्टी और क्रांतिकारी आंदोलन का इतिहास आजादी के पहले से शुरू होता है। 1967 में जिले की अमसिन सीट से राजबली यादव विधायक चुने गए थे। लेकिन उन्हें एक षडयंत्र के तहत सजा करा दी गई और वे जेल चले गए। उनकी सदस्यता रद्द हो गई। तब उनकी जगह पर पंडित शंभूनाथ सिंह विधायक हुए। वे भी कम्युनिस्ट थे। राजबली यादव जनपद के बहुत लोकप्रिय और जुझारू नेता थे। कामरेड राजबली यादव और वसुधा सिंह 1930 से ही सक्रिय थे देश की आजादी के लिए। उन लोगों ने जहांगीर गंज थाने पर यूनियन जैक हटाकर तिरंगा फहराया और दरोगा को ऊंट पर बिठाकर सरयू में फेंक दिया। वे जाड़ों के दिन थे। उसके बाद अंग्रेजों ने उनका जबरदस्त दमन किया। उनका घर गिरा दिया गया। उनकी मां ने एक बाग में पनाह ली। वहां बारिश के चलते वे भीगती रहीं और बीमार होकर मर गईं। आजादी मिलने पर राजबली ने सामंतों के खिलाफ संघर्ष किया। उन्होंने अवधी का ड्रामा लिखा। उसका शीर्षक था---धरती हमारी हम धरती के लाल। उसके गीत थे-

गेहुआं कै रोटिया, अरहरिया कै दलिया, दूनौ जुनिया खैबै।
एक और गीत था–दियना घियवा कै जलाई दै आजादी आइब राम।

उनका अन्य गीत था–उठो मजदूरों किसानों कुछ करके दिखा दो। खून पसीना एक में मिलाय दो।। उनके अवधी के नाटक इतने लोकप्रिय थे कि उसे देखने दस दस हजार लोग जुटते थे। उस भीड़ को व्यवस्थित करने के लिए पीएसी लगाई जाती थी। उन्होंने आजादी के बाद भी एक अत्याचारी दरोगा को पेड़ से बांध दिया था। अयोध्या की सीट पर 1948 में समाजवाद के पितामह और अपने को आजीवन मार्क्सवादी कहने वाले आचार्य नरेंद्र देव भी उपचुनाव चुनाव लड़े थे। हालांकि कांग्रेस ने गोविंद बल्लभ पंत के नेतृत्व में उस चुनाव को सांप्रदायिक बना दिया और बाबा राघव दास को खड़ा करके आचार्य नरेंद्र देव को हरा दिया। इस सीट पर जनमोर्चा जैसे देश के पहले सहकारी अखबार के संस्थापक हरगोविंद जी भी चुनाव लड़े और उनके उत्तराधिकारी शीतला सिंह भी। पंडित शंभू शरण सिंह के बेटे हरिनारायण सिंह भी चुनावी मैदान में उतरे। वे सभी कम्युनिस्ट रहे हैं। सूर्यकांत पांडेय बताते हैं कि यहां कम्युनिस्ट आंदोलन के पतन की वजह भाजपा द्वारा अयोध्या को हिंदुत्व की प्रयोगशाला बनाया जाना तो है ही लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि जब 1993 में सपा और बसपा का गठबंधन हुआ तो दलितों ने कम्युनिस्टों का साथ छोड़ दिया। उसी के दो साल बाद मित्र सेन यादव भी समाजवादी पार्टी में चले गए। अयोध्या विधानसभा सीट और जनपद की बाकी सीटों की राजनीति जाति और धर्म में बुरी तरह से विभाजित हो चुकी है। इस विभाजन के बीच सूर्यकांत पांडेय वर्गीय राजनीति की मरीचिका तलाश रहे हैं। वे अपने आंदोलन के गौरवशाली अतीत से उत्साहित होते हैं और वर्तमान से निराश हैं। इसीलिए लड़ रहे हैं। हार जीत तो होती रहती है लेकिन आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर क्रांतिकारियों और शहीदों के सपनों के भारत का स्मरण दिलाना ही वे अपना बड़ा योगदान मानते हैं। फैजाबाद (अयोध्या) की जेल में ही 1927 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (एचएसआरए) के सह संस्थापक अशफाक उल्लाह खान को काकोरी ट्रेन डकैती के आरोप में फांसी की सजा हुई थी। उन्हीं की याद में सूर्यकांत पांडेय अशफाक उल्ला मेमोरियल संस्थान चलाते हैं। उन्होंने अवधी के मशहूर शायर रफीक सादानी की शायरी के संकलन का संपादन भी किया है। वे हर साल विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिभाशाली लोगों को माटी रतन पुरस्कार भी देते हैं। वे अपनी पूरी राजनीति और सामाजिक सक्रियता को क्रांतिकारियों के सपनों के संदर्भ में ही देखते हैं। इसीलिए वे कहते हैं कि 27 फरवरी को अयोध्या में मतदान के दिन ही चंद्रशेखर आजाद का शहादत दिवस है।

चौटाला परिवार में अब दिल मिलना मुश्किल, जजपा और इनेलो के विलय पर ओपी चौटाला का बड़ा बयान

चंडीगढ़।

हरियाणा में चौटाला परिवार में अब दिलों का मिलना मुश्किल लग रहा है और ऐसा लगता है कि परिवार में कभी समाप्त न होने वाली दूरी हो चुकी है। जननासक जनता पार्टी के अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला के परिवार में एकता की पेशकश को जिस तरह से उनके पिता ओमप्रकाश चौटाला ने जिस तरह से खारिज किया है, उससे साफ होता है कि अब इस सियासी परिवार में एकता संभव नहीं है। हरियाणा में भाजपा-जजपा गठबंधन के विरुद्ध तीसरा मोर्चा बनाने की संभावनाओं के बीच इनेलो प्रमुख ओमप्रकाश ने साफ कर दिया है कि उनके बेटे अजय सिंह चौटाला के नेतृत्व वाली जननायक जनता पार्टी और इनेलो का आपस में विलय किसी सूरत में संभव नहीं है। सजा पूरी करने के बाद जेल से रिहा हुए अजय सिंह चौटाला ने कहा था कि यदि उनके पिता ओमप्रकाश चौटाला चाहेंगे तो इनेलो व जजपा एक हो सकते हैं। इसके नियम और शर्तें क्या होंगी, यह बाद की बात है। ओमप्रकाश चौटाला और अभय चौटाला हालांकि पहले भी यह कई बार कह चुके हैं कि इनेलो का जजपा में विलय संभव नहीं, लेकिन जब भी विलय की संभावना बनती है तो अजय चौटाला अपने पिता और छोटे भाई के पाले की तरफ गेंद सरका देते हैं। चौटाला परिवार में चल रही इस गेंदबाजी से पुराना वर्कर असमंजस में है। इनेलो प्रमुख ओमप्रकाश चौटाला 87 साल की उम्र के बावजूद राजनीतिक तौर पर खासे सक्रिय बने हुए हैं। आजकल वह प्रदेश के दौरे पर हैं और लोगों के शादी-ब्याह तथा सामाजिक कार्यक्रमों में पूरी सक्रियता से भागीदारी कर रहे हैं। उम्र के इस पड़ाव में भी चौटाला मीडिया के सवालों का बखूबी सामना करते हैं और उनके बखूबी जवाब देते हैं। उनके बेटे इनेलो महासचिव अभय चौटाला हरियाणा में गठबंधन की सरकार के विरुद्ध तीसरा मोर्चा बनाने की संभावनाएं तलाश रहे हैं। अभय इस मोर्चा में पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह और पूर्व सीपीएस रामपाल माजरा सरीखे ऐसे दो दर्जन नेता शामिल हो सकते हैं, जिनका हरियाणा की राजनीति में वजन रहा है

और हाल-फिलहाल उनकी अपने मौजूदा दलों में अधिक पूछ नहीं है।

अभय चौटाला की सीएम मनोहरलाल से मुलाकात पर चर्चाएं तेज

अभय चौटाला की पिछले दिनों मुख्यमंत्री मनोहर लाल से भी मुलाकात हुई है। हालांकि अभय के विरोधी उनकी मुख्यमंत्री से मुलाकात को केसरिया और हरे रंग के मिश्रण से जोड़कर देख रहे हैं, लेकिन सूत्रों का कहना है कि अभय ने ऐलनाबाद उपचुनाव के दौरान सीएम द्वारा की गई घोषणाओं को पूरा कराने के लिए मनोहर लाल से मुलाकात की है। जेबीटी शिक्षक भर्ती मामले में सजा पूरी कर लौटे जजपा अध्यक्ष अजय चौटाला के समर्थक अभय चौटाला और मनोहर लाल की मुलाकात को सियासी चश्मे से देख रहे हैं, लेकिन साथ ही उन्हें यह भी लगता है कि जजपा के लिए यह मुलाकात किसी तरह का नुकसान पहुंचाने वाली बिल्कुल भी नहीं है। इस मुलाकात से दुष्यंत समर्थक बेचिंत हैं। अजय चौटाला ने जेल से रिहाई के तुरंत बाद कहा था कि यदि बड़े चौटाला चाहेंगे तो इनेलो व जजपा के एक होने की उम्मीद बन सकती है, लेकिन ओमप्रकाश चौटाला ने साफ कर दिया है कि दोनों दल किसी सूरत में अब एक नहीं हो सकते। अब बात बहुत आगे तक बढ़ चुकी है। इनेलो के सामने राजनीतिक उतार-चढ़ाव आते रहे हैं और एक दिन वह इससे उबर जाएगी। चौटाला ने एक उदाहरण के जरिए यह संदेश देने की कोशिश की है कि इनेलो की दरियादिली की वजह से भाजपा हरियाणा में कई बार सत्ता में भागीदार रही है।

वाजपेयी के साथ चौटाला ने याद किए अपने पुराने रिश्ते

ओमप्रकाश चौटाला कहते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी की चाह के बावजूद उनकी सरकार में हमारा कोई मंत्री नहीं था। वाजपेयी सरकार जब सत्ता से बाहर हुई तो इनेलो के वोट की वजह से ही वह वापस सत्ता में लौटी। हरियाणा में भाजपा 45 सीटें चाहती थीं। उस समय मनोहर लाल भाजपा के संगठन महामंत्री थे, लेकिन भाजपा भी यह मानकर चल रही थी कि सीटों के बंटवारे का अनुपात भले ही कोई भी रहे, लेकिन मुख्यमंत्री चौटाला को ही बनना है। ऐसे में दोनों दलों के हित-अहित आड़े नहीं आए।

चौटाला ने मानी मुलायम के परिवार में एकता की ताकत

इनेलो प्रमुख ओमप्रकाश चौटाला राजनीति में परिवार की ताकत को नजरअंदाज भी नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के नतीजों से जुड़े सवाल पर कहा कि वहां मुलायम सिंह यादव का परिवार पूरी तरह से एक हो गया है। इस वजह से भाजपा के सामने सरकार बनाने की दिक्कतें खड़ी हो गई हैं। चौटाला बोले कि मैं न तो ज्योतिषी हूं और न ही पत्रकार, लेकिन इतना दावे से कह सकता हूं कि भाजपा दोबारा सत्ता में नहीं आ रही है। मुलायम सिंह के परिवार की एकजुटता से जब सपा सरकार में आ सकती है तो हरियाणा में चौटाला परिवार एक क्यों नहीं हो सकता? इस सवाल पर बड़े चौटाला अपने नेतृत्व वाली पुरानी इनेलो सरकार की उपलब्धियां और भविष्य का एजेंडा बताने लगे।

एक नजर

हिसार से हरिद्वार के लिए दौड़ेगी बस : रूट और टाइमिंग निर्धारित; पानीपत डिपो की पहल; सुबह 5 बजे चलकर दोपहर 3 बजे पहुंचेगी

पानीपत । (वेब वार्ता) हरियाणा के हिसार जिले से हरिद्वार की बस शुरू हो गई है। पानीपत डिपो की पहल से हिसार की जनता को पहली बार यह सौगात मिली है। पानीपत रोडवेज डिपो की बस संख्या एचआर67ए 9314 हिसार से हरिद्वारा जाएगी। पानीपत डिपो के जीएम कुलदीप जांगड़ा का कहना है कि बस सर्विस से एक ओर जहां यात्रियों को सुविधा होगी। वहीं दूसरी ओर राजस्व का भी फायदा होगा। पानीपत डिपो की बस सुबह 5 बजे हिसार डिपो से रवाना होगी। हांसी, नारनौल, जींद होते हुए सुबह 9 बजे पानीपत पहुंचेगी। पानीपत से 9:15 बजे चलेगी और शामली, मुज्जफरनगर, रुड़की होते हुए दोपहर 3 बजे हरिद्वार पहुंचेगी। इसी बस सर्विस को आने वाले समय में ऋषिकेश तक पहुंचाने की प्लानिंग चल रही है। इसके लिए मुख्यालय के संज्ञान में बात डाल दी गई है।

फतेहाबाद में सड़क दुर्घटना में 2 युवकों की मौत : हड़ोली में बाइकों की आमने-सामने टक्कर में दोनों के चालकों की जान गई; गांव में पसरा मातम

फतेहाबाद । हरियाणा के फतेहाबाद में रविवार रात गांव हड़ोली के पास हुकमावाली रोड पर 2 बाइकों की आमने-सामने हुई जबरदस्त टक्कर में 2 युवकों की मौके पर मौत हो गई। एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अग्रोहा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। हादसे के बाद से गांव हड़ोली में मातम पसरा है। पुलिस युवकों के शवों का पोस्टमार्टम कराने की तैयारी में है। प्राप्त जानकारी के अनुसार रविवार को करीब 8.30 बजे गांव हड़ोली निवासी रेशम सिंह और जज सिंह बाइक से गांव की तरफ जा रहे थे। इसी दौरान गांव का गगनदीप भी अपनी बाइक से गांव हुकमावाली से अपने गांव आ रहा था। गांव के समीप ही दोनों बाइकों में आमने सामने की टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भयानक थी कि दोनों बाइकों भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। बाइक सवार तीनों युवक सड़क पर गिरने के बाद बेहोश हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही युवकों के परिजन और ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंच गए। टक्कर के बाद दोनों बाइक चला रहे युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक पर बैठा युवक जज सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों ने ही दुर्घटना होने के बाद इस की सूचना गांव वालों व पुलिस को दी। दुर्घटना की सूचना जैसे ही गांव में पहुंची तो पूरे गांव में ही मातम छा गया और देखते ही देखते घटनास्थल पर गांव वालों की भीड़ उमड़ पड़ी। घटनास्थल पर पहुंचे नागपुर पुलिस चौकी के इंचार्ज व उनकी टीम ने तत्परता दिखाते हुए गंभीर रूप से घायल हुए युवक को अग्रोहा मेडिकल उपचार हेतु भेज दिया। पुलिस ने दोनों मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर अस्पताल के मोर्चरी हाल में भेज दिया। दोनों मृतकों का सोमवार को पोस्टमार्टम किया गया। पुलिस इसके लिए परिजनों के बयान दर्ज करने में लगी है।

रोहतक में किराना दुकान से 50000 की चोरी : 47000 नकद और बाकी की सिगरेट की डिब्बियां ले गए; मकान में ही है शॉप, भनक तक नहीं लगी

रोहतक । (वेब वार्ता) हरियाणा के रोहतक जिले में चोरों ने एक किराने की दुकान को निशाना बनाया है। चोर दुकान का ताला तोड़कर गल्ले से 47 हजार की नकदी सहित हजारों रुपए की सिगरेट की डिब्बियां ले गए हैं। पीड़ित दुकानदार ने थाना आईएमटी में चोरों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। पुलिस चोरों की तलाश का रही है। रोहतक के गांव भलौठ निवासी मनोज ने बताया है कि उनके मकान के ही एक हिस्से में उनकी किराना की दुकान है। रात को आए चोरों ने मकान में घुसने के बाद दुकान का ताला तोड़ दिया। चोरों ने यह काम इतनी सफाई से किया कि घर में सो रहे लोगों को पता तक नहीं चला। सुबह आंख खुली तो दुकान के गेट का खुला मिला। शिकायतकर्ता मनोज ने बताया कि चोर एक दिन पहले ही उनके गांव के ही प्रकाश की किराना की दुकान को भी निशाना बना चुके हैं। नकदी सहित दुकान से 20 हजार रुपए का सामान चोर ले गए थे। उस मामले में भी चोरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है, लेकिन अभी तक चोरों का कोई सुराग नहीं लगा है। वहीं मामले में आईएमटी थाना पुलिस का कहना है कि चोरों की तलाश की जा रही है। जल्द ही वह गिरफ्त में होंगे।

मां-बेटी ने निगला जहर, इलाज के दौरान मां की मौत, बेटी की हालत गंभीर

भिवानी (हरियाणा) । भिवानी के उत्तर नगर क्षेत्र में मां-बेटी द्वारा जहरीला पदार्थ निगलने का मामला सामने आया है। मामले की सूचना मिलने पर परिजनों ने मां-बेटी को शहर के एक निजी अस्पताल में दाखिल करवाया, जहां उपचार के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया। वहीं उसकी बेटी की हालत गंभीर बताई जा रही है। मामले की सूचना मिलने पर महिला के मायके पक्ष के लोग भी अस्पताल पहुंचे। अनाजमंडी पुलिस चौकी से जांच अधिकारी एएसआई धर्मबीर शव को कब्जे में कर पोस्टमार्टम कार्रवाई के लिए नागरिक अस्पताल पहुंचे, जहां सोमवार सुबह पोस्टमार्टम कार्रवाई के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने इस संबंध में इत्तफाकिया मौत मामले की कार्रवाई की है।

नवजोत सिंह सिद्धू की खिलाफत करने वाले अमृतसर के पांच कांग्रेस पार्षदों पर कार्रवाई की तैयारी

चंडीगढ़। कांग्रेस के पंजाब प्रदेश प्रधान नवजोत सिंह ने 5 पार्षदों को 6 साल के लिए पार्टी से बर्खास्त करने आदेश दिए हैं। हालांकि अभी सिद्धू ने चिट्ठी पर साइन नहीं किए हैं। पार्टी इन पार्षदों के खिलाफ कार्रवाई करने जा रही है। जिन पार्षदों पर कार्रवाई की जाएगी उनमें वार्ड नंबर 47 से जतिंदर सोनिया, वार्ड नंबर 47 से लाडो पहलवान, वार्ड नंबर 24 से राजिंदर सैनी, वार्ड नंबर 32 से राजेश मदान व वार्ड नं. 18 के पार्षद संदीप कुमार शामिल हैं। इससे पहले कांग्रेस के पंजाब प्रभारी हरीश चौधरी ने हरमिंदर जस्सी, केवल ढिल्लो, तरसेम डीसी, अमरीक ढिल्लो, सतकार कौर और दलजीत राजू को पार्टी से बर्खास्त किया था। बता दें, नवजोत सिंह सिद्धू अमृतसर पूर्वी विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में हैं। यहां से अकाली दल ने पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया को चुनाव मैदान में उतारा है। यहां कड़ा मुकाबला है। ऐसे में कुछ पार्षदों द्वारा पार्टी के खिलाफ जाकर सिद्धू का विरोध किया। इससे पार्टी उनके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर चुकी है। बता दें, मतदान से दो दिन पहले अमृतसर पूर्वी के चार पार्षद अकाली दल में शामिल हो गए थे। मेयर करमजीत सिंह रिंटू सहित दस कांग्रेसी पार्षद अलग-अलग पार्टियों में जा चुके हैं। इसमें सिद्धू की खासमखास पार्षद राजेश मदान, राजिंदर सैणी, जसविंदर सिंह लाडो पहलवान के अलावा जिला कांग्रेस कमेटी की पूर्व प्रधान व पार्षद जतिंदर सोनिया शामिल हैं। यह चारों पार्षद सिद्धू के हलके से संबंधित हैं।

हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, राज्य में नहीं होगी पांचवीं व आठवीं की बोर्ड परीक्षा

चंडीगढ़। आठवीं की बोर्ड परीक्षा को लेकर हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य में अब आठवीं की बोर्ड परीक्षा नहीं होगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि इस साल पांचवीं और आठवीं की बोर्ड की परीक्षाओं को नहीं लिया जाएगा। सीएम ने कहा कि कोविड-19 के कारण बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाई, इसलिए फिलहाल एक साल के लिए बोर्ड की परीक्षाएं स्थगित की गई हैं। सीएम ने कहा मुद्दे पर 25 फरवरी को बैठक बुलाई गई है, लेकिन अभी अगर बैठक बुलाए जाने की जरूरत होगी तभी बैठक करेंगे। बता दें, हरियाणा में आठवीं की बोर्ड परीक्षाओं के विरोध में सभी निजी स्कूल एसोसिएशन लामबंद हो गई थी। हालांकि हरियाणा स्कूल लेक्ररर एसोसिएशन (हसला) फैसले के फैसले के समर्थन में थी। हसला ने इसी सत्र से आठवीं की बोर्ड परीक्षाएं लेने की वकालत करते हुए कहा था कि शिक्षा विभाग पीछे हटा तो राज्य स्तरीय आंदोलन से पीछे नहीं हटेंगे। बोर्ड परीक्षा का विरोध कर रहे निजी स्कूलों की 12

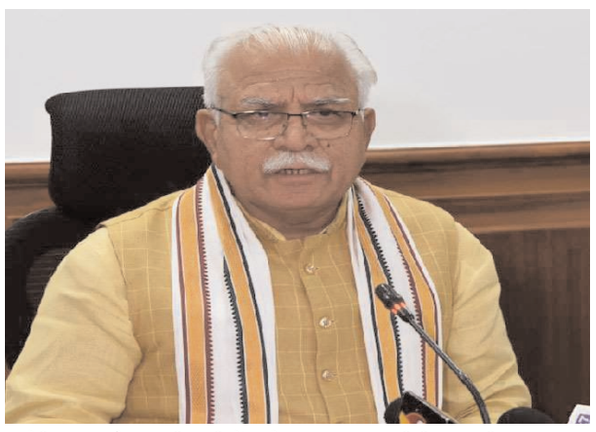

एसोसिएशन के पदाधिकारियों को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 25 फरवरी को बातचीत के लिए बुलाया है। इनमें हरियाणा प्रोग्रेसिव स्कूल एसोसिएशन, निसा, हरियाणा यूनाइटेड स्कूल एसोसिएशन, करनाल इंडिपेंडेंट स्कूल एसोसिएशन, हरियाणा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन, एफआइसीसीआइ अराइज, रिकोगनाइज्ड यूनाइटेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन, प्रोग्रेसिव प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन, यमुनानगर डिस्ट्रिक पब्लिक स्कूल एसोसिएशन, पब्लिक स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन पलवल, प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन कैथल और गोल्डन वैली स्कूल के प्रतिनिधि शामिल हैं। हसला के राज्य प्रधान सतपाल सिंधु ने कहा कि सरकार द्वारा इसी सत्र से आठवीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा करवाने का निर्णय सराहनीय है। इससे सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले गरीब के छात्रों को उच्च गुणवत्तापूर्वक शिक्षा हासिल हो सकेगी। परंतु प्राइवेट स्कूल संगठन सरकार के इस महत्वाकांक्षी निर्णय में बार-बार अड़चनें डाल रहे हैं। संगठन मांग करता है कि सरकार प्राइवेट स्कूल संगठनों के विरोध को दरकिनार कर छात्र हितों को देखते हुए इसी सत्र से आठवीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा करवाए। आठवीं तक विद्यार्थी को फेल न करने की नीति से पढ़ने व सीखने के स्तर में लगातार गिरावट आई है। हसला के प्रदेश प्रेस सचिव अजीत चंदेलिया ने कहा कि केंद्र सरकार ने भी नई शिक्षा नीति में तीन कक्षाओं की परीक्षाएं लेने का प्रावधान किया है।

हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने इसी सत्र से आठवीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा करवाने की सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली है। लगभग सभी सरकारी व काफी प्राइवेट स्कूल आठवीं कक्षा के छात्रों का रजिस्ट्रेशन करके एनरालमेंट की फीस भी जमा करा चुके हैं। यदि सरकार प्राइवेट स्कूलों के संगठन के दबाव में वार्षिक परीक्षा नहीं करवाती है तो यह प्रदेश के लाखों छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करना होगा।

पंजाब में बहुकोणीय मुकाबला : त्रिशंकु विधानसभा की तरफ हो सकता है मतदाताओं का रुझान, किसी के लिए आसान नहीं सत्ता की डगर

चंडीगढ़ ।

पंजाब में मालवा, माझा और दोआबा में इस बार कांटे की टक्कर है। मुकाबला बहुकोणीय है लेकिन सत्ता की डगर किसी के लिए आसान नहीं है। वजह साफ है कि इस बार पंजाब में सत्ता के चाहने वाले कई हैं। अब तक की सियासत में कांग्रेस और अकाली ही आमने -सामने होते थे। पिछले चुनाव से आम आदमी पार्टी मैदान में आ गई और अपनी जगह बनाई। लेकिन इस चुनाव में मतदान प्रतिशत कम होने के कारण समीकरण बदल गए हैं। भाजपा, शिअद, कांग्रेस, आप, संयुक्त समाज मोर्चा के अलावा दोआबा में हाथी भी चिंघाड़ने के लिए तैयार खड़ा है। कांग्रेस कैप्टन को अलविदा कहने के बाद जहां वापसी के लिए बेताब हैं, वहीं अकाली दोबारा से सत्ता की हनक पाने की कोशिश कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी पिछली बार रह गई कसर पूरा करना चाह रही है तो भाजपा पंजाब में सत्ता की भागीदारी के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।

सूबे में पिछले एक सप्ताह से चल रही सियासी हवा अचानक बदल गई है और चुनाव आते आते समीकरण बदल गए हैं। उत्तर प्रदेश के बाद भाजपा ने अपना पूरा जोर पंजाब में लगा दिया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार जनसभाएं कीं और अमित शाह को मैदान में उतारा। राष्ट्रवाद को मुददा बनाकर चुनाव में कूदी भाजपा पंजाब में इस बार धर्मगुरुओं और डेरों के सहारे अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रही है। वहीं, आम आदमी पार्टी मालवा में भगवंत मान के सहारे सत्ता का सिंहासन पाना चाह रही है। पिछली बार की गलतियों को दरकिनार कर आप ने पंजाब में सधा हुआ चुनाव लड़ा है। लेकिन ऐन वक्त पर अरविंद केजरीवाल के ही पुराने साथी कुमार विश्वास ने उन पर हमला बोल दिया। विश्वास के हमले के बाद भाजपा और कांग्रेस सहित अन्य सभी दलों ने आप को निशाने पर ले लिया। भाजपा के पुराने दोस्त रहे अकाली इस बार अलग चुनाव लड़ रहे हैं। डेरा सच्चा सौदा के वोटों की आस दोनों ही दलों को है। इसके अलावा पंथक वोट के सहारे अकाली फिर से मैदान में आना चाह रहे हैं। जबकि 22 किसान जत्थेबंदिया का संयुक्त समाज मोर्चा किसानों के दम पर पंजाब में ताल ठोक रहा है। बलबीर सिंह राजेवाल मोर्चे के मुख्य चेहरे हैं। अभी हाल ही में किसान आंदोलन से वापस हुए लोग पंजाब पहुंचे हैं। संयुक्त मोर्चा को पूरी उम्मीद है कि सत्ता न सही लेकिन सत्ता में दखल पूरा होगा।

मतदान कम और पार्टियां अधिक

पंजाब में 15 साल बाद मत प्रतिशत गिरा है, अन्यथा पंजाबी मतदान में आगे रहे हैं। 2007 में 77.20 प्रतिशत मतदान हुआ था और अकालियों ने सरकार बनाई थी। 2012 में 78.30 प्रतिशत मतदान हुआ और अकालियों की वापसी हुई। 2017 के चुनाव में 77.20 प्रतिशत मतदान हुआ तो कैप्टन अमरिंदर सिंह की ताजपोशी हुई। इस बार मतदान कम 68.03 प्रतिशत हुआ है और सत्ता की चाबी भी सभी दल चाह रहे हैं।

रोहतक में दारोगा का 16 वर्षीय बेटा लापता : घर से शाम के समय निकला था और अब तक नहीं लौटा, सरपंच ताऊ ने दर्ज कराया केस

रोहतक ।(वेब वार्ता) हरियाणा के रोहतक जिले में एक दारोगा का 16 वर्षीय बेटा घर से कहीं जाकर लापता हो गया है। परिजनों ने उसे काफी तलाश किया है, लेकिन उसका अभी तक कोई सुराग नहीं लग रहा है। मामले में लापता किशोर के ताऊ व गांव के सरपंच ने थाना बहुअकबरपुर में केस दर्ज कराया है। पुलिस किशोर की तलाश कर रही है। उसे जल्द ही सकुशल बरामद कर लिया जाएगा। रोहतक के गांव मुरादपुर टेकना के सरपंच सुनील ने बताया है कि उनके भाई सब इंस्पेक्टर अनिल का बेटा 16 वर्षीय लक्की रविवार शाम 7 बजे घर से बिना बताए कहीं चला गया। जब वह देर रात तक नहीं लौटा तो उसको काफी तलाश किया गया, लेकिन अभी तक उसका कोई सुराग नहीं लगा है। 16 वर्ष में ही उसका 6 फीट कद है और 100 किलो वजन है। वहीं रोहतक के सिटी थाना क्षेत्र के एक गांव से एक युवक की पत्नी घर से बिना बताए लापता हो गई है। युवक मजदूरी करता है और काम पर गया हुआ था। उसके पीछे पत्नी कहीं चली गई। अभी दोनों की शादी को एक साल ही हुआ है। पीड़ित ने मामले में पत्नी की गुमशुदगी का केस दर्ज कराया है। पुलिस महिला की तलाश कर रही है।

सिरसा में डॉक्टर से मांगी 20 लाख चौथ: विश्वास अस्पताल के डॉ. अशोक गुप्ता को मारने की धमकी भी दी; पुलिस ने दर्ज किया केस

सिरसा ।

हरियाणा के सिरसा में एक मनोरोग चिकित्सक डॉ. अशोक गुप्ता से बदमाशों ने 20 लाख रुपए की चौथ मांगी है। बदमाश खुद को कुख्यात नीरज बवाना गैंग का बता कर बार-बार फोन कर उसे रकम के लिए धमका रहे हैं। रुपए न देने पर जान से मारने की धमकी दी जा रही है। सिविल लाइन थाना पुलिस ने डॉक्टर की शिकायत पर अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार डबवाली रोड पर सांगवान चौक स्थित विश्वास मनोरोग व नशा मुक्ति अस्पताल के चिकित्सक डॉ.अशोक गुप्ता को बदमाशों ने शनिवार रात को फोन कर 20 लाख रुपए तैयार रखने को कहा। फोन करने वाले ने खुद को दिल्ली के कुख्यात नीरज बवाना गैंग का बदमाश बताया। धमकी भरे फोन आने से भयभीत डॉक्टर गुप्ता रविवार सुबह कुछ साथी डॉक्टरों के साथ

थाना सिविल लाइन पहुंचा और चौथ मांगने की शिकायत दी। उन्होंने बताया कि उसे पैसे देने के लिए बार बार धमकाया जा रहा है। सिविल लाइन थाना इंचार्ज सुरेश कुमार ने बताया कि उन्हें डॉक्टर अशोक गुप्ता की तरफ से शिकायत मिली है। मामला दर्ज कर लिया है और इसकी जांच की जा रही है।

मामला रंगदारी का बताया जा रहा है। जांच में पूरा मामला साफ हो जाएगा कि कौन सा गैंग डॉक्टर से रंगदारी (चौथ) मांग रहा है सिरसा में बदमाशों द्वारा किसी से चौथ मांगने का यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले कांग्रेस नेता एवं पूर्व मंत्री जगदीश नेहरा के बेटे सुरेंद्र नेहरा और शहर के ष्ट ब्लॉक में रहने वाले एक व्यक्ति से भी चौथ मांगी जा चुकी। कॉल करने वाले मामले में दोनों अपने आप को अलग अलग गैंग के सदस्य बता रहे है। बढ़ते रंगदारी के मामलों को लेकर शहर के लोग ख़ौफज़द हैं।

भ्रष्ट ई.ई अशोक कुमार के भ्रष्टाचार की कमान बी.डी.शर्मा के हाथों में

सिचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, सी.डी-11 में करोड़ो का भ्रष्टाचार.....सी.बी.आई जांच की मांग।

कार्यपालक, सहायक व कनिष्ठ अभियंता बने भ्रष्टाचारी नंबर-1

सी.डी-11 के पूर्व ई.ई अशोक कुमार, ए.ई, जे.ई ने किए करोड़ो के वारे न्यारे...

विकास एवं निर्माण कार्यो में घोटाला कर लगाई गई व लगाई जा रही, बेहद घटिया निर्माण सामग्री की शिकायतो के आगे केजरीवाल प्रशासन ने टेके घुटने

पूर्व ई.ई अशोक कुमार के बाद ई.ई बी.डी.शर्मा डूबे भ्रष्टाचार के आकंड में कमिशन खोरी का सिलसिला लगातार जारी

नीलोठी एक्सटेंशन, चन्द्र विहार के बड़े नाले पर नये पुल के निर्माण कार्य में किया करोड़ो का घोटाला

श्री खंडा साहिब चौक, चंदर विहार में कई पार्को के विकास एवं निर्माण कार्य में किया करोड़ो का घोटाला

शिकायते होती रही परन्तु भ्रष्टाचारियों का भ्रष्टाचार बढ़ता रहा, आज भी नही लगी रोक !

अध्यक्षः अपराध एवं भ्रष्टाचार निरोधक मोर्चा

विज्ञापन-जनहित में जारी.....

निगम में भाजपा की छवि को कालिक पोत रहे है भ्रष्ट अभियंता

करोल बाग जोन, भवन विभाग बना भ्रष्टाचार का अड्डा!

अवैध निर्माण की काली कमाई से अभियंता से उपायुक्त तक बने "अडानी"

उ.दि.न.नि के मुख्य सतर्कता अधिकारी मंगेश कश्यप बने मूक दर्शक कब तक चलता रहेगा भ्रष्टाचार का खेल

करोल बाग, नई दिल्ली

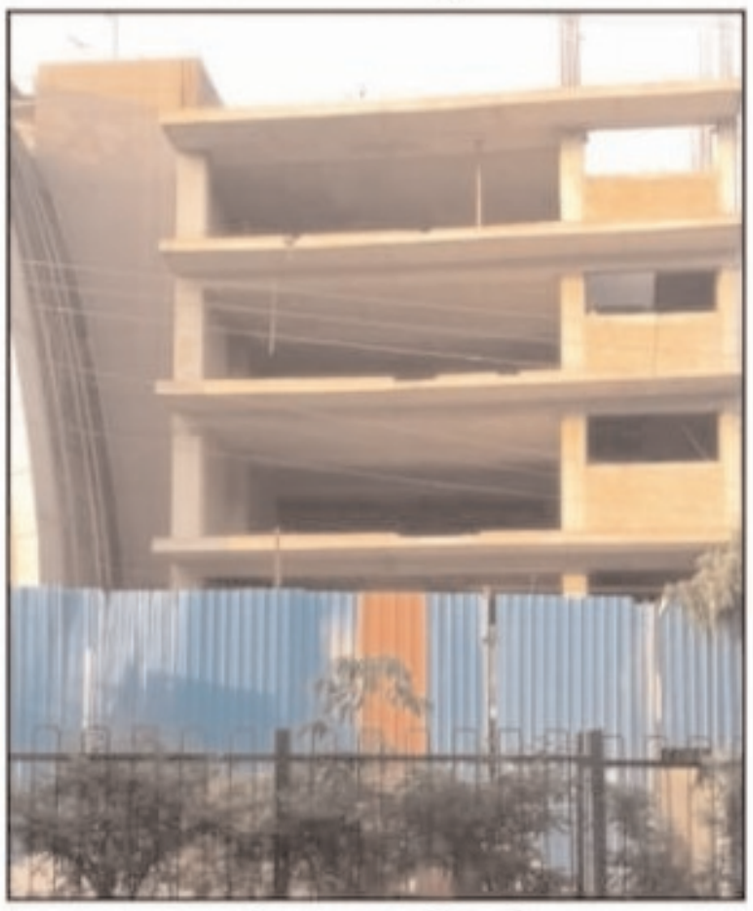

करोल बाग, नई दिल्ली

करोल बाग, नई दिल्ली

करोल बाग, नई दिल्ली

करोल बाग, नई दिल्ली

करोल बाग, नई दिल्ली

करोल बाग जोन में बिल्डर माफिया का राज सारे वार्ड बनते जा रहे है स्लम युक्त हर वार्ड में चार से पांच मंजिला, बेसमेन्ट सहित अवैध निर्माण धड़ल्ले से किया जा रहा है। अभियंताओं की काली कमाई चल-अचल व बेनामी सम्पत्ति की श्रीमान निदेशक जी, सीबीआई, भारत सरकार से जांच की मांग।

अध्यक्ष: अपराध एवं भ्रष्टाचार निरोधक मोर्चा

विज्ञापन-जनहित में जारी.....

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार भारती ने वन्दना ऑफसेट प्रिन्टर्स, ए-9, सराय पीपलथला एक्स. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया। सम्पादक : विजय कुमार भारती, मो0 : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/2001/08863)

लो.नि.वि के स्ट्रीट स्कैपिंग प्रोजेक्ट डिवीजन, ई.ई के संरक्षण में

दिल्ली की बड़ी-बड़ी चौड़ी सड़को को सौंदर्यकरण के नाम पर किया छोटा, लंबे सर्विस रोड़ खत्म, विकास एवं निर्माण कार्यो में घटिया निर्माण सामग्री और सैकड़ो की संख्या में हरे-भरे पेड़ो को काटकर किया करोड़ो रूपये का घोटाला

कार्यपालक, सहायक व कनिष्ठ अभियंता बने लो.नि.वि के सबसे बड़े डकैत

एक ओर दिल्ली में सड़कों पर भारी भरकम जाम जिससे चारो ओर प्रदूषण ही प्रदूषण और वही दुसरी ओर सड़को को छोटा किया जा रहा है क्या ऐसे रूकेगा दिल्ली का जाम, दुर्घटना व प्रदूषण

नेताजी सुभाष प्लेस से लेकर रिठाला मैट्रो स्टेशन तक रोड़ नं. 41 व 41ए का निर्माण..

मायापुरी से मोती बाग जंक्शन का निर्माण.....

"गुरू हरिकिशन मार्ग" शकूरपुर से रानी बाग की ओर का निर्माण.....

बी.आर.टी कैरिडोर की तरह होगा प्रोजेक्ट फेल? बनाने और उखाड़ने में होगी करोड़ो रूपये की बबार्दी?

सौंदर्यकरण की आड़ में किया हजार करोड़ का नुकसान, नये बने बौक्स ड्रैन, फुटपाथ, ओवर फुटब्रिज, डैन्स कारपेट, ग्रिले, बस स्टेण्ड, बिजली के खम्बे, स्ट्रीट लाईटे और लाखो मीटर तार किये गए नष्ट?

अभियंताओं और ठेकेदार की मिलीभगत से नष्ट हुए करोड़ो के सामान हो बेचा कोढीयों के भाव में कबाड़ीयों की दुकानो पर।

लो.नि.वि के मुख्य अभियंताओं की आंखो पर चढ़ा भ्रष्टाचार का पर्दा व जेबे हुई गरम

दिल्ली की बड़ी-बड़ी चौड़ी सड़को का किस प्रकार का निर्माण कार्य किया जा रहा है?

जब सड़के छोटी हो जाएगी तो जाम, दुर्घटना और प्रदूषण बढ़ने का जिम्मेदार कौन होगा?

दिल्ली की जनता के द्वारा दिया गया करोड़ो के टैक्स की बबार्दी की जिम्मेदारी कौन लेगा?

डिजाईन/योजना बनाने वाले अधिकारियों और पूर्ण प्रोजेक्ट की श्रीमान निदेशक, सी.बी.आई, भारत सरकार से जांच कराई जाए?

सचिवः जन कल्याण न्याय समिति दिल्ली

विज्ञापन-जनहित में जारी.....